SHRI S. JAIPAL REDDY: Let the Minister say what Sikander Bakhtji has said.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Jaipal Ji, that matter is closed. I am not allowing any more discussion on that. I have now to go to the next item. *(Interruptions)*

SHRI S. JAIPAL REDDY: Let the Minister agree to what the Leader of the Opposition says. He says he will go as per the law.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: We may agree on certain points also, but I object to ...*(Interruptions)*

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am also in agreement with them. It is the Minister who is not respecting the sentiments of the entire Opposition. The entire Opposition wants him to stay his action. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Jaipal Reddy, you cannot impose. *(Interruptions)* Madam, they cannot do like this. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, please sit down. *(Interruptions)* Please take your seat. Just one second, please. You had objected to the Bill. I am repeating it again that he came here to day to move the Bill. He come to my chamber and talked to some Members of Parliament. I wanted Mr. Jaipal Reddy to be there. Therefore, I searched for him. Then on persuasion the Minister said: "All right, whatever you suggestion is, I will bring a comprehensive legislative legislation in the next session." Now, the Minister said he was not going to do which is illegal, which is not within the rules. I think that is sufficient. Mr. Minister, you can go now. *(Interruptions)* That matter is over now. I am only dealing with it this much. I am not going into the merits. I cannot discuss the merit of a Bill which is not under discussion. The Bill is not before the HouSe for discussion. So, we cannot discuss it. I now go on to the next item— The Constitution (Eighty-first Amendment) Bill, 1994. Dr. Jagannath Mishra.

THE CONSTITUTION (EIGHTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 1994

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्तावा करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

महोदया, संविधान के नवम् अनुसूची में, विभिन्न राज्यों से प्राप्त भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण देने की दृष्टि से, सम्मिलित करने के लिए यह विधेयक लाया गया हैं। ...(**व्यवधान**)....

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : मिश्र जी, जब हाऊस नार्मल हो जाए तब बोलिएगा। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।

उपसभापति : बोलिए बोलिए। मिश्र जी का क्या यह पहला बिल हैं? मैंडेंन परफोरमेनन्स हैं आपकी ? और वह भी कंस्टीट्यूशन ...(**व्यवधान**)....

डा. जगन्नाथ मिश्र : जी ...(**व्यवधान**)....

श्री दिग्विजय सिंह : पहला बिल हैं इनका।

डा. जगन्नाथ मिश्र : महोदया, इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संविधान के नवम् अनुसूची में 27 अधिनियमो को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा जा रहा हैं। विभिन्न राज्यों से समय-समय पर जो अधिनियम प्राप्त हुए हैं, उन्हें संवैधानिक संरक्षण देने का हैं। इनमें से बिहार राज्य के 9, कर्नाटक का एक, केरल के 2, उड़ीसा का एक, राजस्थान के 3, तमिलनाडु के 4 और पश्चिम बंगाल के 7 अधिनियम हैं। इन 27 अधिनियमों में से 3 मुख्य अधिनियम भी हैं जिन्हे पहली बार इस नवम् अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए ला रहे हैं। The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956, the Bihar Privileged Persons. Homestead Tenancy Act, 1947 and the West Bengal land Reforms Tribunal Act, 1991.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : मिश्र जी, आप हिन्दी में बोलिए। ...(**व्यवधान**)....

उपसभापति : अभी आप उन्हे बोलने दीजिए। यह कोई तरीका नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)....

श्री शंकर दयाल सिंह : इन्होने हिन्दी में शुरू किया, जरा हिन्दी में बोलिए।

डा. जगन्नाथ मिश्र : मैं हिन्दी में ही कह रहा हूं वह मैं आपके नाम बता रहा था।

मैडम, हम कह रहे थे कि 27 अधिनिपयम हैं, जो समय समय पर राज्यों ने मुख्य अधिनियमों में संशोधन हेतु पारित किए हैं, उन संशोधनों को संवैधानिक संरक्षण हेतु पारित किए हैं, उन संशोधनों को संवैधानिक संरक्षण दिया जा रहा हैं। उन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में इसलिए सम्मिलित किया जा रहा हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों में इन अधिनियमों को संवैधानिक बिन्दुओं पर चुनौती दी गई। उन्हे संविधान का संरक्षण प्राप्त नहीं था, इससे राज्य सरकारों को कठिनाई हो रही हैं। इस उदेश्य से इन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा रहा हैं। जैसा कि सदन को जानकारी हैं, मानीनय सदस्य जानते हैं कि पहली बार 1951 में इस प्रकार का संविधान संशोधन हुआ था, जो प्रगतिशील कार्यक्रम सरकार चलाना चाहती थी, उनमें उस समय मूल अधिकारों के उल्लघंन के कारण जो अवरोध उत्पन्न किए जा रहे थे, उन अवरोधों से इन कानूनों को मुक्त कराने के लिए इन्हे संविधान का संरक्षण देने और संविधान के 14 तथा 19 अनुच्छेद के तहत जो भाग 3 के अंतर्गत संविधान में लोगों को प्राप्त हैं उससे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की और सामाजिक न्याय के कार्यो में रूकावट न पड़े, इसी वजह से पहली बार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह संविधान संशोधन पेश किया था। उस समय 13 ऐसे अधिनियम सम्मिलित किए गए थे इस सूची में। उसके बाद समय-समय पर अभी तक 255 अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, इनमें से 222 ऐसे हैं जिनका संबंधी सीधे भूमि सुधार के कार्यो से हैं और पिछले वर्षो में सारे देश में बड़ी मुस्तैदी से भूमि सुधार के कार्य सम्पन्न हुए हैं, खास तौर से जो भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम है, उसका कार्यान्वयन बड़ी तत्परता से हुआ हैं। लोगों में कुछ भ्रान्तियां हुई इस संबंध में कि सरकार के आर्थिक उदारीकरण की वहल से या नई आर्थिक नीति की वजह से भूमि सुधार के कार्यक्रमों में कुछ विलम्ब किया जा रहा हैं या भूमि सीमा का पुनर्निधारण किया जा रहा हैं। भारत सरकार की ओर से हमने पहले भी स्पष्ट किया हैं और आज भी सदन के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि भूमि सुधार के प्रति भारत सरकार प्रतिबद्व हैं। जो भी नीति रही हैं भारत सरकार की 1972 मे मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो मार्गदर्शक सिद्वान्त तय किए थे, उन्हे सारे देश के संघ राज्यों ने स्वीकार किया और तदनुसार सभी राज्यो में भूमि सुधार के कार्यक्रम तत्परता से चलाए जा रहे हैं और आज तक स्थिति यही हैं कि सारे देश में 15,99,226 रिटर्न दाखिल किए गए है, उन रिटर्नो में से 15,81,723 का निष्पादन हो गया हैं और इस कानून के तहत अभी तक देश में 74,09,613 एकड़ जमीन सरकार अतिरिक्त घोषित करके उसमें से 65,41,659 एकड़ प्राप्त कर ली हैं। उसमें से 51,46,443 हजार एकड़ जमीन गरीबों के बीच में बांटी जा चुकी हैं। उसमें से अनुसूचित जाति के 17,91,263 लोग लाभान्वित हुए हैं और जनजातियों के 7,03,845 लोग लाभान्वित हुए हैं और दूसरे लोगों में 24,99,193 लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह हैं कि जितनी प्राप्त हुई हैं उसमें से 10,64,606 एकड़ जमीन विभिन्न न्यायालयों में मामलो में फंसी हई हैं, जो गरीबो में बांटी नहीं जा रही हैं। इसलिए सरकार को ओर से कोशिशें हो रही हैं कि सभी राज्यों में तत्परता से जमीन को निकाला जाए और मुख्य मंत्रियों को हमने खास तौर से कहा हैं कि जितनी तत्काल वितरण योग्य जमीन प्राप्त हैं, उस जमीन को बांटा जाए। जो जमीन मुकदमों में फंसी हुई हैं, 323B अनुच्छेद के अंतर्गत अभिकरण स्थापित करके विवावादास्पद जमीन के मामलों को निष्पादित कराकर गरीबों के बीच में बांटी जाएं।

और यह भी कहा गया हैं कि इस समय लगभग चार लाख एकड़ जमीन सरकार ने आरक्षित कर रखी हैं दूसरे कार्यो के लिए। उस संबंध में भी हमने राज्य सरकारों से कहा हैं कि जमीन भूमिहीनों के लिए हैं, उस जमीन को आप दूसरे कार्यो में न लगाएं, बल्कि भूमिहीनों के बीच में यह जमीन बांटी जाए। ऐसा हमने साफ तौर पर कहा हैं। साथ-साथ जो हमारे पट्टेदार हैं, शेयर क्रॉपर हैं उन्हे अधिकार दिए जाएं और उनके नाम अंकित किए जाएं और हमने यह भी कहा हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में रययत और तैय्यत पट्टेदारों के हक निर्धारित किए हैं, अंकित किए गए हैं, उसी तरह से सारे देश में एक अभियान चलाकर सभी राज्य सरकारें इस काम को करें। यह भी हमने साफ तौर पर कहा हैं। यह भी हमने राज्य सरकारों से कहा हैं कि हदबंदी कानून में जो त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं जिनकी वजह से विवाद होते

हैं या जिनकी वजह से मुकदमें होते हैं उस कानून को आप फिर से दुरूस्त करने की कोशिश करिए और प्रस्ताव लाइए।

इस तरह से सरकार के निश्चय को हम यहां पर दोहराते हैं कि हदबंदी कानून तत्परता से लागू किया जाए और ऐसे सभी कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो और सरकार का यह निश्चत हैं कि गरीबों के हित में इस कानून का अधिक से इस्तेमाल हो और जो जमीन हैं उसको गरीबों के बीच में तत्काल बांट कर सामाजिक न्याय का जो कार्यक्रम भारत सरकार का हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो तत्सरपता दिखाई हैं एक विशेष अभियान हदबंदी कानून के बारे में, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उस निर्णय के मुताबिक प्रधान मंत्री जी की ओर से सभी राज्यों को, मुख्य मंत्रियों को कहा गया हैं हदबंदी कानून को और भूमि विवाद संबंधी कानून को तत्काल लागू करें और उनको सुविधा देने के उद्देश्य से ही यह संवैधानिक संरक्षण देने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव इस सदन के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

The *question was proposed.*

उपसभापति : श्री संघ प्रिय गौतम , संक्षेप में बोलिएगा।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : संक्षेप में ही बोलूंगा।

उपसभापति महोदया, हमारा देश कल्याणकारी राज हैं। हमने अपने देश के शोषित, गरीब, पीड़ित, कमजोर, भूमिहीन सब लोगों के हित में, विकास और कल्याण के लिए संकल्प लिया हैं और देश की सत्ता में, देश की सम्पत्ति में, देश के संसाधनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हमने बीड़ा उठाया हैं, हमने फैसले लिए हैं।

[माननीय उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) पीठासीन हुए]

हम सत्ता, सम्पत्ति और संसाधनों का विकेन्द्रीकरण भी चाहते हैं। मैं पूरी बात करने से पहले विश्वास दिलाना चाहता हूं मिश्र जी को, कि मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो सात राज्य जिनसे संबंधित यह विधेयक हैं , मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। कि यह वह राज्य हैं जो प्रगतिशील राज्य हैं जिनके कदम प्रगति की ओर हैं। यह वह राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में पिछले कई वर्षो से

सामाजिक उथल-पुथल हो रही हैं सोशल अपहिवेल्स जहां पर हो रहे हैं खास तौर से बिहार, और यह जो सामाजिक उथल-पुथल हैं इसका एकमात्र कारण गांव में खेती या खेती की जमीन हैं। गावं के लोग 75 परसेंट जो इस देश में रहते हैं, उनका जीवन खेती से जुड़ा हुआ हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भू-स्वामी हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो खतिहर मजदूर हैं। काफी दिनों तक यह गले से गला मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन अनेक अवसरों पर विवाद खड़े होते हैं, टकराव होते हैं, जानें जाती हैं और सामाजिक तनाव बढ़ाता हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि इसका एकमात्र कारण भूमि हैं। इसलिए इस देश में भूमि सुधार होना बहुत आवश्यक हैं, भले ही कारण कुछ भी रहे हों,लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन पहली बार हुआ और सिडीकेट और इंडीकेट कांग्रेस बनी, मैं दाद देना चाहता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, कि उन्होने तीन कामों की घोषणा की थी। एक तो गरीबी को दूर करने के लिए उन्होने बीड़ा उठाया था और यह कहा था कि जोत की जमीन पर पाबंदी होगी और शहर की जमीन पर भी सीमा लगेगी। उसी समय से यह चकबंदी और हदंबदी कानून लागू हुए। जो जमीन निकली ग्राम समाज की जमीन थी , वह इन खेतिहर मजदूरों को वितरित हुई। लेकिन मुझे अफसोस हैं, कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी के जमाने में जहां कानून बहुत अच्छे थे, बड़ी संख्या में राजे-महाराजे, जमींदार, भूमि स्वामी कांग्रेस में छाए हुए थे। वे कांग्रेस में मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, ब्लॉक प्रमुख थे, बड़े-बड़े पदों पर थे। यह घोषणा की गई लेकिन इस कानून का क्रियान्वयन करने में सात-आठ वर्ष का समय लगा दिया गया। लिहाजा जो चकबंदी के बाद, हदबंदी के बाद जमीन निकल करके सरकार के कब्जे में आनी चाहिए थी, वह नहीं आई और फर्जी पट्टे देकर लोगों ने अपने कुत्तो के नाम, बिल्लियों के नाम, भैंसे-भैसों के नाम, भोडें-भौड़ियों के नाम करा दिए क्योंकि आम तौर से बड़े लोगों के कुत्तों के नाम हीरा होते हैं, मोती होते हैं, बिल्लियों के नाम पूसी होते हैं। देखने में ये नाम आदमियों के मालूम होते हैं लेकिन वे होते कुत्ते और बिल्ली हैं। इसलिए जितना लाभ इस भूमि-सुधार का गरीबों को पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंच पाया। जितनी जमीन गरीबों को मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई। जो बंटनी चाहिए थीं, वह नहीं बंट पाई और दूसरी परेशानी यह हुई कि जब न्यायालयों में ये विवाद खडे हुए तो इनकी पैरवी सरकार के लोगों ने या प्रशासन

के लोगों ने नहीं की क्योंकि उनकी अधूरी मंशा इस जमीन को निकालने और वितरित करने की थी। आज भी बड़ी संख्या में उच्च न्यायालयों में ,सर्वोच्च न्यायालयों में हदबंदी से संबंधित अनेको बड़े-बड़े विवाद लंबित हैं, विचाराधीन हैं और लाखों एकड़ जमीन जो निकल कर आनी चाहिए और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आबंटित होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक मंत्रालय बहुत बड़ा, जिसके स्वयं इंचार्ज प्रधान मंत्री जी हैं, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं और मंत्री जी स्वयं जिन्होने यह विधेयक प्रस्तुत किया हैं, बड़े डंके की चोट पर कहा जाता हैं कि बीस हजार करोड़ रूपया इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए रखा गया हैं और ग्रामीण विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा हैं खेती का, भूति का बंटवारा, भूमिहीनों को भूमि का बंटवारा। गांवों के अंदर जब तक भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी, उनको मान नहीं मिलेगा उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनको कुटीर उद्योग-धंधे लगाने का मौका नहीं मिलेगा और गांवों के अंदर जब तक कुटीर उद्योग धंधे नहीं होंगे, खेती पर आधारित उद्योग धंधे नहीं होंगे, गांवों का विकास नहीं होगा। गांवों के लोगो को रोजगार नहीं मिलेगा, इस दृष्टि से भी भूमि का आबंटन बहुत आवश्यक हो गया है।

तीसरी बात, एक तरफ जहां हम भूमिहीनों को भूमि वितरित करना चाहते है, बहुत से भूमिहीन मजबूरी कें जब उनके पास थोड़ी सी भूमि हैं, उसे वे बेच लेते हैं उस बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए, यह भी भूमि-सुधार का एक अंग हैं और इन विधेयकों से यह बात प्रतिबिंबित होती हैं कि जिनके पास थोड़ी भूमि हैं, वे अपनी भूमि को वितरित न करें।

इसके अलावा बहुत से लोगों की भूमि गिरवी रख ली जाती हैं खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में। गिरवी रखने के बाद उस भूमि का लाभ खेती के माध्यम से उन भूमि स्वामियों को नहीं मिल पाता और उनके हाथ में वह भूमि चली जाती हैं। इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए।

सरकार अपने उद्यमों के लिए या संस्थानों के लिए या सार्वजानिक हित के कार्यो के लिए भूमि का अध्यापन करती हैं, अध्यापित करती हैं भूमि को, ऐक्विजिशन करती हैं, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान भूमि स्वामियों को या छोटे काश्तकारों को होता हैं। इसलिए भूमि-सुधार बहुत आवश्यक हैं। जिस प्रकार के उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किये हैं उन्ही से संबंधित यह विधेयक उन राज्य सरकारों ने, राज्य विधान मंडलों ने पारित किये हैं और कभी-कभी यह देखा गया हैं कि मौलिक अधिकारों का बहाना करके जो काम गरीबों के हित में किये जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर लोग मौलिक अधिकारों का बहाना करके न्यायालयों की शरण ले लेते हें और विकास कार्यो में बाधा पैदा हो जाती हैं। गरीबों के विकास और कल्याण में अवरोध पैदा हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग गरीबों के हित में, विकास में बाधा पैदा न कर सकें न्यायालयों की शरण फंडामैंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का बहाना करके न ले सकें। यह सब रोकने के लिए इन विधेयकों का संविधान की नौंवी अनुसूची में लाना बहुत आवश्यक है और यही मंशा सरकार की रही हैं। लेकिन अभी विधेयक को प्रस्तुत करते समय जब मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होने अपना सारा जोर इस बात लगाया कि कितनी जमीन उन्होने निकाली हैं और कितनी जमीन उनके कब्जे में हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मंत्री जी जरा गौर से सुनिए। मिश्र जी, आप कोटेया साहब से बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। आपने कहा कि हम राज्य सरकारों को निर्देश दे रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित कीजिए। नैनीताल के तराई क्षेत्र जिसे भाभर कहते हैं, तराई भाभर खीरी लखीमपुर, पीलीभीत, इसमें हदबंदी कानून आज तक लागू नहीं हुआ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (**उत्तर प्रदेश**) : किच्छा भी।

श्री संघ प्रिय गौतम : अब वह तराई का इलाका कहलाता हैं। नैनीताल का तराई भाभर क्षेत्र, जिसमें किच्छा तहसील हैं, काशीपुर हैं, टनकपुर हैं, और भी अनेक क्षेत्र हैं, पीलीभीत, खीरी लखीमपुर हैं यह वह जिले हैं, जहां पर हदबंदी कानून आज तक लागू नहीं हुआ। मुझे ध्यान हैं एक जिलाधिकारी ने नैनीताल में जब यह कानून लागू करना चाहा तो कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने मैं नाम नहीं लूंगा, बाधा डालकर उसको रोक दिया और लाखों एकड़ जमीन, एक-एक आदमी के नाम 10-10 हजार बीघा, 5-5 हजार बीघा जमीन हैं। उसके दो नुकसान होते हैं। गन्ने की खेती वहां होती हैं। अभी दो वर्ष पहले आपने देखा, आतंकवादी पंजाब से और दूसरे प्रदेशों से नेपाल के रास्ते इस क्षेत्र में जाकर गन्नों की खेतों की बीच में शरण लेते थे और इनके मालिक डर के कारण, भरय के कारण, लालच के कारण या रिश्तेदारी के

मारे उन्हे शरण देते थे। आज भी वह खतरा बना हुआ हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपकी बात सच हैं और वास्तव में आप प्रदेशों को निर्देशित कर रहे हैं और आप भूमिहीनों को भूमि बांटना चाहते हैं तथा भूमि सुधार के कानूनों को लागू करना चाहते हैं तो आप जहां-जहां पर भी हदबंदी कानून लागू नहीं हुए, वहां तुरंत लागू करवाइए और जहां आप मामूली बात का बहाना करते हैं 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। देश के हित तथा कल्याण में जो सरकार बाधक हो तथा जो देश के हित, विकास और कल्याण में जो सरकार रूची न लेती हो, ऐसी सरकार को भंग करना चाहिए। चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो। आखिर हम कहां तक विदेशों से कर्जा लेते रहेंगे? हम कब तक अपने लोगों को भूखे मारते रहेंगे? कब तक हम गरीबों का मजाक उड़ाते रहेंगें? हम कहां से इनके लिए रोजी-रोटी लाएंगे और कहां से कपड़ा और मकान लाएंगे? केवल यही हैं कि हम इस देश की हदबंदी से निकलने वाली जमीन को इनको बांटें। इनको कुटीर उद्योग दें, इनको छोटे-छोटे काम दें। यह तभी संभव होगा जब हम भूमि सुधारों को करें। जैसा कि उपसभापति महोदया ने कहा था कि समय थोड़ा लिया जाए। मैं अधिक समय न लेकर एक तो यह कहना चाहूंगा कि कभी-कभी प्रश्न उठता हैं कि अनइकॉनॉमिक होल्डिंग, जो छोटी खेती हैं, वह अलाभकारी हैं। बात देखने में बड़ी सुन्दर लगती हैं लेकिन तन ढांकने के लिए, अपने परिवार को सर्दी, गर्मी , बरसात और धूप से बचाने के लिए बड़े चौराहे पर जिन्दगी गुजारने के बजाय दो गज जमीन में एक झोपड़ी अपनी होना आदमी को सम्मानित और स्वाभिमानी बनाता हैं। उनमें सम्मान पैदा करता हैं। इसलिए छोटी जमीन भले ही हो गांव में रहने वाला व्यक्ति उस पर अपना मकान बना लेगा। अगर वह दूध देने वाली गाय या भैंस पालेगा तो उकसे लिए चारा भी बोएगा। चारे के लिए उसे दूसरे बड़े काश्तकार के खेत में नहीं जाना पड़ेगा। पिटाई से बच जायेगा। उसको खेती में जाने से रोका नही जायेगा। इसके अलावा अपने खाने के लिए साग, सब्जी भी उसमें उगायेगा स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने तो – जय जवान जय किसान—का नारा लगाते समय यह कहा था कि अपनी छत पर, अपने आंगन में भी खेती करो। गांव मे दो-तीन-चार बीधा जमीन अगर एक आदमी को मिल जायेगी तो वह दाल उगा लेगा, सब्जी उगा लेगा, अपने पशु का चारा उगा लेगा, सब्जी उगा लेगा, अपने पशु का चारा उगा लेगा, अपनी झोपड़ी बना लेगा। ....(**व्यवधान**)....

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, one clarification. I am on a point of order. Our learned brother is advancing an argument on a subject which is not relevant to the Bill. The point is whether the Acts mentioned in clause 2 of the Bill should included in the Ninth Schedule or not and whether protection should be given. We are not discussing the Land Reforms Bill or any such thing. Let him confine himself to the subject-matter of the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Sangh Priya Gautam, please conclude.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें जितने विधेयक है यह सब भूमि सुधार से सम्बन्धित हैं।

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : उससे सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : भूमि सुधार पर ही मंत्री महोदय ने भाषण दिया हैं। यह कहा हैं कि हमने इतनी जमीन निकाली हैं, इतनी जमीन बांटने जा रहे हैं, इतनी हमारे कब्जे में हैं। यह आपके भाषण में हैं जो ऑन रिकार्ड हैं और मैं उसी पर बोल रहा हूं

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): This is all relevant. But you please conclude.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं खत्म कर रहा हूं। सरकार की नीयत ठीक हैं लेकिन सरकार की जो प्रक्रिया हैं वह बहुत ढीली हैं और बड़ी कमजोर हैं, बड़ी सुस्त है। प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और उमसें गति आनी चाहिए। राज्यों को निर्देशित करना चाहिए कि हदबंदी कानूनों को तुरन्त लागू करे, जो यह विधेयक पारित किया गया हैं इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए। मंत्री महोदय जो 9वीं सूची में जिन विधेयकों को शामिल कराने के लिए लाये हैं इसका मैं समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Naraya-nasamy. Please keep in mind the time.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I will be very brief, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You know all the Members should be present. Normal-

ly we finish the debate latest by 5.30 P.M. so that there could be voting.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister has moved the Eighty-first Constitution Amendment bill on the basis of the letters written by the State Governments of West Bengal, Tamil Nadu, Rajasthan, Kerala, Orissa, Karnataka and Bihar, who have gained experience through the implementation of the Land Reforms Act. Sir, it is the policy of every State, irrespective of the political party which rules the State, and the Centre that the land held by any individual or family should not exceed a certain limit. It has been prescribed by the Government and it has been accepted by various State Governments that if it is fertile agricultural land, the holding could be 10 acres to 18 acres and if it is dry land, it could be 54 acres. These are the ceiling limits. In our country we find people holding lands in *benami.* As far as the farming community is concerned, it is a major issue which has been haunting them. Our slogan was that the land should be given to the tiller of the soil. But, when the legislations were passed by various State Governments for the implementation of this Act so that the surplus land could be given to the landless people who would be the beneficiaries, the courts came in the way and because of the procedural wrangles and other legal procedures the delay occurred. Therefore, the hon. Minister has come forward with this bill so that this matter cannot be challenged in the courts. Sir, in my State when the Land Refors Act was passed, but was not implemented, we went before the review Committee. The reply given by the State administration was that as the matter is in the Supreme Court, therefore, we are not in a position to get the surplus land and give it to the poor landless labourers. Sir, it is a sorry state of affairs. When we wanted to implement this Act, the courts came in the way. The Government should find a way out. Sir, in two States, i.e. Kerala and West Bengal, the Land Reforms Act has been successfully implemented. As I just said about *benami* land holdings, I am pained to say that in some of the States the landlords are having lands even in the name of their dogs. They are having lands in the names of the people who are not their relatives. This kind of *benami* transaction is going on. Sir, the former Chief Minister, Shri Madhavsinh Solanki, is here.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Dr. Mishra is also here.

SHRI V. NARAYANASAMY: He is here to explain it. He will explain ho^ he implemented this Act. But, I am told tfi'at in Bihar it has not been implemented in right earnest and it has also not been implemented in Uttar Pradesh. Let me make it very clear. Many State Governments have not given effect to the legislation I am not quoting any Congressp-ruled State or non-Congress-ruled State. Let us have a uniform policy. I am grateful to various State Governments, who, irrespective of their "party affiliations, have recommended that it should be put in the Ninth Schedule. ITierefore, by providing for this provision in the 9th Schedule, by amending the Constitution, it will benefit lakhs and lakhs of people of the farming community and the poor agricultural labourers. The benefit which has been given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is enormous. About 17.7 lakh Scheduled Caste people and 7.19 lakh Scheduled Tribe people have been benefited. This is a novel scheme by which the people are being benefited. I want the hon. Minister to do something about the *benami* holdings. People write documents in various names. That has to be stopped. The State Government should be authorised to investigate into such *beiiami* holdings and action should be taken against those people. The procedure that has been evolved for the purpose"- of giving land to the agricultural beneficiaries should be simplified. The big States like

Bihar and Uttar Pradesh, should be given a directive on the basis of this amendment. The State Governments should unscrupulous follow the procedure and see that the beneficiaries are selected immediately. The backward people living in these States have been deprived of their rights. I support the bill and I want the hon. Minister to implement it and see that the benefit is passed on to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and also the OBCs who have been deprived of agricultural land.

SHRIMATI RENUKA CHOW-DHURY (Andhra Pradesh): Sir, I would like to add one point to what my colleague said just now. I want to place this on record. It is such a tragedy—our agricultural land policy vis-s-vis what we give to the industry. Here, we dangle a carrot before the farmers and offer them land as tokenism, whereas, an industry can buy 200 acres of land. They can just free buy land anywhere. There is no restriction. No revenue has been shown. No revenue has been reflected in this Budget. If You really examine it, there is no revenue and there lies the tragedy. We need to reexamine them. We just give fertilizer subsidy, which is an eye wash. There is no revenue... *(Interruptions)...* Let them declare agriculture as an industry. You give 200 acres of land to multinational companies and they grow potatoes and sell potato chips. But my farmer cannot do that. He is restricted and farming becomes uneconomical in the case of small holdings. The market rates fluctuate and no floor support rates are given to the farmers. I have no words to express the true tragedy. We are not seeing agriculture as India's backbone. We talk about the poor fanners. During the election time, everybody talks about the farmer. It is said *Annadata sukhji bhava.* I wanted to place this on record.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 1994 मंत्री जी ने पुर:स्थापित किया जिसका उद्देश्य कोई बहुत बड़ा नहीं हैं। जैसे इन्होने कहा कि इसके स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स को देखने से पता चलता है कि कई प्रान्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार संबंधी जो कानून पारित हुए हैं उन कानूनों को लिटीगेशन से बचाने के लिए नाईथ शेड्यूल में जोड़ा जाना, यह मानस हैं। उद्देश्य तो अच्छा हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही। आज की बहस को शुरू करते हुए हमारे साथी गौतम जी ने कुछ बातों को कहा जो सत्य भी हैं। मंत्री जी स्वयं बिहार के रहने वाले हैं बिहार के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं । अपने मुख्य मंत्रित्व काल में भूमि सुधार संबंधी क्या क्या काम इन्होने किये हैं अगर उसी का ब्यौरा दे देते तो हम अंदाजा लगाते कि इन्होने क्या किया हैं।....(**व्यवधान**)....

डा. जगन्नाथ मिश्र : बहुत कुछ किया हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती कमला सिन्हा : यह हम लोगों को मालूम हैं।

डा. जगन्नाथ मिश्र : आप लोगों का जीरो हो जाएगा।

श्रीमती कमला सिन्हा : पोल मत खुलवाइए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Is this about Bihar?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT-ISH AGARWAL): Don't interrupt, please.

SHRIMATI KAMLA SINHA: This is a dialogue between the former Chief Minister of Bihar and me.

यह ठीक हैं कि हमारे बिहार प्रांत और उड़ीसा तथा राजस्थान में लैंड टेनेंसी शुरू से रही हैं। इनमें छोटे किसानों—मारजिनल एण्ड स्माल फारमर्स की संख्या अधिक हैं। बीच में बड़े भूमिपतियों से जमीन लेकर जमीन बांटरने की कोशिश हुई। यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। विनोबाजी का भूदान आंदोलन चला। उसमे लोगों ने जमीन दान भी की। यह भी बात सही हैं। उस भूदान की जमीन गरोबो में बांटी भी गयी कुछ हद तक लेकिन दखलदहानी उनकी नहीं हुई। गरीबों को उस जमीन के ऊपर वह अधिकार नहीं दिलाया जा सका क्योंकि भूमिपति जो बलवान होते हैं उनकी जमीन में भूमिहीनी खेतिहर काम तो कर सकते हैं लेकिन भूमि के मालिक बनकर उसकी फसल काटक अपने घर मे नहीं

5 ले जा सकते हैं। मैंने अनेकों घटनाएं देखी हैं। जगन्नाथजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। छोटा नागपुर में पलामू जिले में एक घटना घटी थी। एक गांव के आदिवासी लोगों ने यह निर्णय लिया था कि हमें जमीन का लाल कार्ड मिला हैं इसलिए इस बार फसल काटकर हम घर ले जायेंगे। फसल काटकर घर ले जाने की तैयारी भी की लेकिन उस गांव के महाजन ने जो एक अत्याचार किया उसका हद का हिसाब नहीं हैं। मास रेप की घटना मैने वहां पहले पहल देखी थी। छोटे बच्चों के साथ अत्याचार मैंने वही पहले पहल देखा। उस गांव का नाम हैं सारोदात? आज भी आप पता लगा सकते हैं। पलामू में भभुआ जिला में वह था। यह तो स्थिति है। अनेकों इलाकों में यह स्थिति हैं और अभी तक जमीन दी नही जा सकी हैं। आज भी दुर्भाग्य की बात हैं कि ऐसे अनेकों इलाकों हैं हमारे प्रांत में जहां एक ही परिवार के पास हजारों एकड़ जमीन हैं और वे मंत्री भी थे, राजा भी थे, सब कुछ थे क्योंकि इस तरह के लोगों को पावर अगर नहीं रहे तो अपनी सम्पत्ति का बचाव वे नहीं कर सकते हैं। फर्जी नाम पर, कोआपरेटिव बनाकर जमीन रख ली, फर्जी नाम पर सारी जमीनें उनके अपने कबजे मे हैं। रजा रजवाड़े के दिन आज भी चल रहे। जमीन बांट दी कागजों पर लेकिन भूमिपति आज भी हैं। शान वही हैं। रस्सी जल गयी, ऐठन नहीं गयी हैं। वह दूर करना बड़ा मुश्किल का काम है। उड़ीसा आदि अन्य प्रांतों की बात में क्या कहूं हमारे प्रांत बिहार मे जो अपना देखा हुआ हैं उसी की बात कह रही हैं।

ठीक हैं हमारे अन्य लोगों ने और हमने भूमि मुक्ति आंदोलन बहुत चलाया। बहुत संघर्ष किया। भूमि मुक्ति आंदोलन में मार भी हम लोगों ने बहुत खायी जेलों में भी हम लोग गए। थोड़े दिन के लिए उनकी बेदखली भी रोकी लेकिन असलियत में हम उनके दुख दर्द को दूर नहीं कर पाएं।

नेपाल की तराई में हमारे यहां थारूहाट हैं। वहां एक आदिवासी ट्राइब हैं। लोग यह कहते हैं कि भगवान बुद्व उसी थारू जाति के थे। थारूहाट में जमीन का बंटवारा हो गया था। थारूओं को जमीन दी गयी थी। उसके बाद क्या हुआ मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहती हूं। जगन्नाथ जी को नाम मालूम हैं। बड़े बड़े लोग जो उस समय मंत्री थे और मुख्य मंत्री भी बन गए, सारे थारू लोगों को जमीन अपने नाम से कब्जे करा ली। थारू बेदखल हो गए। उनके पास आज जमीन नहीं हैं।

यहां तो स्थिति हैं। आप आज इसको 9th शिड्यूल में एड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हैं। जब से बिहार में नये वातावरण की शुरूआत हुई हैं, खासकरके जयप्रकाश जी के आंदोलन से, 1974 के आंदोलन से तब से आम लोगों में एक जागरूकता आई हैं। उस जागरूकता के कारण लोगों ने अपने अधिकारों को पहचाना हैं। जब से उन्होने अपने अधिकार को पहचानना शुरू किया हैं तो उनको बेदखल करना मुश्किल हो रहा हैं।

5p.m.

लोग मरने-मिटने को तैयार हो रहे हैं, लोग बेदखल होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेदखल करना मुश्किल हो रहा हैं। हमारे यहां छोटा नागपुर का इलाका हैं। वहां लैंड टेनेसी एक्ट हैं। आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन भाई लोग बड़े चालाक होते हैं। लोग बाहर से जा करके बड़े लोग हो गए हैं। वे क्या करते हैं। आदिवासियों की लड़की या लड़का से ब्याह कर लिया। लड़की से ब्याह-शादी कर लिया। झूठ-मूठ की शादी रचा कर उनकी जमीन को अपने नाम से लिखवा लिया और उसके बाद उस लड़की के घर से निकाल दिया। जमीन के मालिक बन बैठे। छोटा नागपुर लैंड टेनेसी एक्ट की भी धज्जी उड़ा दी। उस समय जो प्रशासन हमारे वहां था वह चुपचाप बैठा रहा, कनाइवेंस करता रहा, छोटा नागपुर के आदिवासियों की कोई रक्षा नहीं कर सके। इस तरह एक-एक अंचल की कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी हैं। रोने के जैसी कहानी हैं। आंसूओं से भरी हुई कहानी हैं। भूमिहीन खेत मजदूरों की आसुंओ से लिखी हुई कहानी हैं। छोटे किसानों के आंसूओं से लिखी हुई कहानी हैं। मार्जनल फार्मर्ज की आंसूओ से लिखी हुई कहानी हैं। हमारे यहां अब यह कानून में हैं कि कंसोलिडेशन आफ् होल्डिंग हो रहा हैं और उसका काम चला भी कुछ दिन, लेकिन आधा ही रह कर ठप्प हो गया, क्योकि वह लोगों को सूट नहीं करता कि कंसोलिडेशन आफ् होल्डिंग हो, जमीन का पास बुक हो, जमीन का मल्कीयत सही मायने में तय हो जाए तो यह बातें तो लोगों को सूट नहीं करती हैं।

to those who are at the helms of affair. 3TO आज जगन्नाथ जी का नाम भी उसमें से एक हैं। ....(**व्यवधान**)....

Because he was the Chief Minister. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : अब तो जगतनाथ हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती कमला सिन्हा : हां, अब तो जगतनाथ हैं, यह भी बात आपने सही कही। जगत का नाथ, उसका नाम लेने से ही लोगों का परित्राण हो जाएगा, स्वर्गलाभ होगा। इस दुनिया में कुछ मिला, नही मिला स्वर्गलाभ शायद हो जाए। यह बात तो हैं। तो महोदय, में यह कहना चाहती हूं कि शायद केन्द्र में आने के बाद कुछ इनकी दिव्या-दष्टि खुल गई और लगा कि यह सब कानून को इकट्ठा कर लें नाईन्थ शैड्यूल में हम डाल दें ताकि कानून पचड़ा नहीं हो, लोगों को परेशानी नहीं हो। ठीक हैं, बहुत अच्छी बात हैं। आप इसको कर लीजिए। आपने दूसरा जो प्रांत जिसके बारे में आपने कहा कि जैसे उड़ीसा जो बिहार की हालत हैं उड़ीसा की करीब-करीब एक ही जैसी हैं। राजस्थान की हालत भी उसी तरह की हैं। जहां फ्यूडलिज्म रहा हैं वहां समाज व्यवस्था एक ही तरह की रही हैं। वहां एक ही तरह की लोगों की शोषण करने की प्रवृत्ति रही हैं भूमिपतियों के द्वारा भूमिहीनों का शोषणा करना। तो यह सब प्रांत जहां फ्यूडलिज्म रहा हैं वहां यह परिस्थिति आज भी हैं। बेनामी जमीन लोग काम करते हैं और लोग सताए जा रहे हैं। मेरा तो यह सुझाव होगा कि पूरा विस्तृत सर्वे कराया जाए कि किसके पास कितनी जमीन हैं। उसका सर्वे हो और उसका रेकार्ड तैयार हो। बारम्बार यह कहा जा रहा हैं कि लैंड पास बुक हम दे रहे हैं। वह भी करके देखिए तो पता चले कि किसके पास कितनी जमीन हैं। अगर किसी का बेनामी जमीन हैं तो जिस व्यक्ति के नमा से वह बेनामी जमीन हैं उसको ढूंढकर उसको जमीन दे दीजिए तो फिर यह सैंकड़ो-हजारों एकड़ जमीन एक-एक लोगों के हाथ में जो रखा हुआ हैं वह तो निकल जाएगा। उससे लोगों को परित्राण तो मिलेगा और गुंडागर्दी और तरह-तरह की सेना जो बन रही हैं। उस सेना की त्रासदी से मुक्ति तो मिलेगी। यह निश्चित रूप से करना चाहिए मंत्री जी, आपको। आप पता नहीं यहां से आकर क्या कर पायेंगे और समय तो आप लोगों के पास बहुत कम रह गया। यह अगस्त का आठवां महीना समाप्त हो रहा हैं और शायद मार्च तक चुनाव हो जाएं। उसके बाद कांग्रेस कहां जायेगी, कोई ठिकाना नहीं , क्या होगा? तो यह थोडा सा समय हैं, कुछ पुष्प लाभ कर लीजिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए तो शायद इतने दिनों का जो काम किया हुआ हैं उस पर शायद कुछ पर्दा पड़ जाए, कुछ शायद सफाई हो जाए और कुछ शायद अच्छा काम आप कर सकें।

इतनी ही बात कह कर मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT-ISH AGARWAL): Dr. Biplab Dasgupta, kindly bear in mind that it is a Constitutional (Amendment) Bill. If the debate is delayed, then the Members will go home and there will be problem. All the Members are supporting this particular Bill. Despite your support, the Bill will not go through unless we conclude early. I know that the subject is very important.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, while supporting the Bill, I would call it a joke, a cruel joke also. The contents of the Bill are what we had been campaigning for many decades. We wanted protection for land reforms under the Ninth Schedule. My party has been demanding this for the last four decades. The Bill has come now. In fact, the Bill was drafted in 1994. It has come for consideration in 1995 and the Bill deals with land reforms legislations which were passed many many years ago in many States. One is from Bihar in 1948. Most of them were passed in the 1950's, 1960's and some in 1970's. I find very few from the nineties except for two in 1990 and 1991 from West Bengal. Most of the other Bills have historical relevance because they have been passed by the State Legislatures long time back. Despite this, protection was not given. What does this mean? It is almost like diagonising the cancer patient and then not doing anything about the treatment, letting the patient die of cancer. Only after the patient has died, you are starting operating on the body to remove cancer. This is exactly what is happening. It is almost like the English proverb, "Botling the door after the horse has fled" because most of the damage has already been done. Land owners, the vested interests have already gone to courts in many cases for many many years. You have not allowed the laws to be properly implemented. And hence the damage has already been done. Even if the Bill was brought in the last year, 1994, then there would have been some time left. Why at

the fag end of the Congress rule are you promising? Because, you want, as Kamla-ji has said, some *Punya.* You want to show that you are in favour of the people. It is almost like the case of Rix Van Winckle or I can give the example of Kumbhakarna in Mahabharat. You have been sleeping for so many years. Most of the damage has already been done. If you were really sincere and serious about the Bill, then this Bill could have been brought not today in 1995 but in 1951! This should have come forty years ago. This forty years' time has been wasted by the Congress party and the Government. This is something which I wanted to put on record. Because this is election year all this concrn for poor, money distribution and all these things are coming.

Apart from this, I would like to make some specific points which I would like the Minister to respond to. Are you really serious about land reforms? I am not sure you are really serious about it. Only the other day the Minister for Agriculture discussed on the draft Agriculture Policy. In that there is not a single word about land reforms. We raised to point out that this question be discussed. Even if it is not there, at least when the Minister was replying, we expected him to say something on land reforms. Not a single word was mentioned.

If you go through the literature of the Government either the report of the Planning Commission or various other reports, it is clear that until 1991 not much was done about land reforms, very little was done. But we had consolation of some good rhetoric. At least it was there in the paper that land reforms were good and the report was sent to Rome. Lots of things were stated about land reforms. I find that even the rhetoric of land reforms was missing in the draft Agricultural Policy. If you mean that the task of land reforms has been completed, that is one thing. But, if the Government is really thinking that land reforms are no longer necessary under the new economic environment, let them be bold and say so. I am challenging them on this point. Let they be bold on this issue and say categorically if they feel that under the new economic policy there is no need for land reforms, that we will understand. We can take recourse to debate point and expose you. But you do not have the guts to say so. So, you do not mention land reforms in the Agriculture Policy. If you do not have land reforms in Agriculture then for what else land reforms are? You have, at the same time, the cheek to bring such a Bill at the fag end of the day which can mean nothing. Apart from that, if you look at some of the specific provisions, for example, you will see that the Ministers of Revenue of different States meet once in two years in Delhi. When they meet they come out with a series of recommendations... Mr. Minister, I want you attention, please. I was saying that the Revenue Ministers of various Sates meet in Delhi, hold conferences a/j'j discuss the land reforms issue. I have seen all the reports so far. They come out with specific recommendations. They say that within such a deadline or within that time this particular programme would be implemented. I would like to know from the Minister as to how many of these recommendations have actually been implemented. If you look at some of the specific recommendations and also the Report of the Planning Commission, it is stated that by the 7th Plan the recording of rights would be completed. We all know how important the recording of the rights is. People do not know what law you pass. Unless the right is properly recorded, the sharecropper, the small farmer, will never be able to get the benefit of the legal system because it would be denied to them. The recording of the rights is very important for everyone who is concerned with the land reforms. Unfortunately, this has not been done yet. The vast majority of the peasants do not know wluit legal rights have been given to them. So, they would

not be in a positiofn to take advantage of it because when it comes to court, it would be shown that they do not have any legal right on the land. They will be denied that. What action is being contemplated by the Government to ensure that the recording of the rights is completed? Another issue that I would like to raise is the question of agricultural labour. There has been a discussion for a long time that there is a need for a Central legislation for agricultural labour because there is a question of the guarantee of their wages, their working conditions, their compensation, their pension and other issues. The Government did draft a Bill several years back. It was* also circulated to the State Governments. The State Governments did send some of the comments. And again, they have been put in the cold storage. Nothing more has been done. I would like to know what has happened to that Bill, whether the Government is serious about it or not, and whether the Government feels it necessary to have a Central legislation on agricultural labour or not. That is the question that I would very much like to ask the Minister. Coming to the land ceiling, in the early days, say, in 1970s or 1980s, the Planning Commission came out with a document revealing the performance of the difference State Government in the matter of land ceiling legislations. Some of the documents have been very well-writtent. I remember some of the documents. Our Vice-Chairman might have also seen some of the documents. Now, over the last nine or ten eyars, I have not seen any report coming out. There has to be a review of the performance of land ceiling legislations. What we have done in West Bengal, apart from anything else, we have implemented the land ceiling laws. It was there eveh\before the Left Front Government came 'to power. There, of course, we introduced our own land ceiling legislation. There are different ways in which the landlords evade the law by getting some exemptions for plantation or orchard or religious trusts. The name of . God is used for evasion which is so common at many places. In West Bengal, we have plugged those loopholes." So, if you talk of plantation, orchard or trust, you do not get any exemption any more. It is because they make legal arrangements for evading the law. So, what I am saying is that the loopholes of land ceiling legislation are well-known. Measures to stop the loopholes are also well-known. What prevents us from implementing ceiling legislation? That is the question which is very important. *(Time Bell rings)* I will take only one minute more. I would request the Minister to consider this. Now, the Minister might say that there the land reforms is a State subject and why the Central Governpnent should be bothered about it. For two reasons, for example, for some of the laws like the Central legislation on agricultural labour

— we are seeking this Central legislation

— apart from the fact that even when the State Government is involved, there have been cases in which the Central Government has used its fiat to ensure conformity of the State Governments with the various pieces of Central legislation.

For example, the Panchayati law. Panchayati law is truly and really a State subject. But the Central Government has passed a law, a Union law which makes it necessary for every State Government to hold Panchayati elections. What I am saying is this. Why can't we have similar laws at the national level which force the Governments at the State level to carry our land reform.

I do not know how it can be done. It should be subejct to discussion with the Revenue Ministers in different States and it should be ensured that the State Governments do take up these policies and implement them. Even in the National Development Council this can be discussed much more seriously. But the point is this. It is not simply what different State Governments are doing. These different State Governments are also run by political parties which are present in

this Parliament. Let all in the Parliament agree that land reform is important and without land reform there cannot be industrialisation because there is not a single country in the world which has developed without land reform. Even South Korea, even Taiwan, certainly Japan, all countries in Europe had to carry out reforms before they could industrialise. And without land reforms there cannot be a market for industrial goods. Purchasing power will be reduced. Taking that into account and also the fact that we are dealing with a large section of the Indian population—majority of the Indian population lives in villages—if we can do something which benefits the majority of the population by way of land reforms, that will do much more substantially than some of the other minor provisions which have been announced either from the Red Fort or from other Press Conferences. If you are really concerned about the poor, if you really want social change, if you really want industrialisation, there is no way that you can go away from land reforms and the seriousness with which the land reforms will be discussed. I would like to emphasise it here, would request the Minister not simply to push through this Bill which is absolutely nothing because already its content has been taken out because it is too late. But still we are supporting it because this is in principle with which we are in agreement. Although it is too late, we are supporting it. But this joke should not be continued. If we are really serious about land reforms, you implement it. If you think in the current economic situation land reform is not necessary, boldly we will take it up as a challenge in the next elections. But don't try to do one thing and say another thing. That would be my request to the Minister. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT-ISH AGARWAL): Shri Margabandu, ᵛour party's time is just three minutes. I will permit you five minutes. Please conclude within five minutes.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Yes. Respected Vice-Chairman, at the outset we welcome this Bill. The reason is that, as early as 1951, under the First Amendment Act, whatever enactments are included in the Ninth Schedule, are protected and it is immunised from court proceedings. So, in that way these bills are sought to be included in these amendments. We welcome it. But still one thing we will have to look into. Even an Act is immunised, we see that several settled laws are unsettled. Even many of the tenancy laws in the Ninth Schedule have been subjected to discussion and discretion of the courts. Several contradictory judgment have been rendered, contradictory to the" immunity given under Article 31(B). But we are not taking any step to settle that position at all. It is high time. I request the hon. Minister to heed this suggestion. All the three limbs of democracy—Legislature, Executive and Judiciary—are independent and at the same time, they are interdependent. At the same time, what is now happening is that there is an erosion into the power of the Legislature. That erosion will lead us nowhere. Though the Ninth Schedule is there and protection is given, several courts are giving several contradictory verdicts. For example, I would like to quote one thing. This Item 257(A) that was included in the Ninth Schedule is in respect of the legislation passed by the Tamil Nadu Government, reserving 69 per cent for the Backward Classes. When immunity under 31(B) is there, it is challenged in the Supreme QJurt. There is a different direction given in the Supreme Court. And then what is the meaning in saying that 31B is on the statute? If there is immunity, and that immunity is overlooked by the Supreme Court, and a different direction is given by the Supreme Court, then, where are we? Everyday, some legislation can be passed. The next day, the judiciary will

pass some other thing, and that judiciary's judgement will be binding on the people. The latest judgement of the court will be the law of the land. What is the position now? Everyday there is a change of laws. Today one judgement is delivered. The next day, another judgement, very contradictory to that, is delivered. Then which will prevail, whether the earlier judgement or the later judgement? The later judgement alone will prevail. If that is so, there certainly confusion is created. Nobody knows the law. What the law is today is not the law tomorrow.' And what is not the law today will be the law tommorrow. The advocates do not know the law. The citizens who are expected to know are not able to know the law. That is why there is mounting of cases in the courts. Rich people are dragging the poor litigants to the courts. There are several hierarchies of the courts. The persons who have more money and other power is only benefited because of the contradictory judgements of the courts. I request you, Sir, that this is high time that a Committee is to set up to deal with the limits of the powers of these three limbs of democracy the Legislature, the Executive, and the Judiciary. Now, there is one thing. Sir, I may be pardoned because I am a practising lawyer and I know some of t'ie practical difficulties in implementing that law.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT-ISH AGARWAL): Lawyers are generally accustomed to agrue to length.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, to drive home a point, I will have to go round and round.

Sir, you take, for example, the Cultivating Tenants Protection Act. How many contradictory and conflicting judgements have been delivered? That Act is given protection under the Ninth Schedule. Then, how have the courts seized power of legislature to give different judgements? What control do we have? Is the Judiciary supreme or the Legislature is supreme? The Legislature in their wisdom have passed certain laws. Taking entirely the circumstances prevailing in that particular State, they legislate certain laws for the benefit of the major weaker sections of the people. Even there, the courts transgress. A judge who is sitting on a pedestal does not look into the common man's feelings. He looks just like a horse having these...

SHRI N.K.P.SALVE: Blinkers.

SHRI R. MARGABANDU: He gives the judgment. He goes by the letter of the law. He completely destroyes the spirit of the law. He completely ignores the spirit behind the legislation enacted by the Legislature. Under such circumstances, the question is whether the judiciary is more powerful than the Legislature. At the same time, we must take steps to see that welfare legislations, taking into account the spirit behind them, are protected, *(time-bell rings).* Saying that it is violative is no good. Therefore, I would respectfully submit that it is high time that we set up some forum to go into this and limit the powers of these three limbs. One should know the particular situation in which a certain legislation was enacted. One should know what is the law. This is not ihe case. That is why cases have been dragged on for decades and generations together. When a person goes to a court of law, when a person takes recourse to the law, he should be able to see the end of his case, at least, in his lifetime. Why do I say this? Because sometimes, generations pass before one sees the end of a case.

Therefore, Sir, I pray to this august body to bestow some thought on this, to limit the powers of these three limbs and see that there is no erosion of their powers; there should not be any encroachment on the powers of another. With these words, I conclude my speech. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT-ISH AGARWAL): Mr. Jalaludin Ansari. Mr. Ansari, this is an important subject, but, unfortunately, your party has only

half-a-minute. However, you can have three minutes.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : आधे मिनट के समय का मतलब यह हैं कि बोलने नहीं देना। इस टाइम के क्या मायने हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं इसलिए कि सात राज्यों में भूमि-सुधार, भूमि हदबंदी कानून लागू करने के लिए और वासगिल का पर्चा देने का जो कानून हैं, वह संविधान की नौवीं अनुसूची में आ जाने से कोर्ट में उसकी चुनौती नहीं दी जाएगी। हम लोगों का व्यावहारिक अनुभव हैं कि सरकार ने जिनको हदंबदी से फाजिल जमीन दी हैं, पर्चा भी दे दिया जिसको लाल कागज कहते हैं लेकिन उस पर कब्जा नहीं दिया हैं और वह लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू तक मुकदमें में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते-जाते रहते हैं। सरकार का इन कानूनों के माध्यम से जमीन देने का जो लक्ष्य हैं, वह पूरा नहीं हो पाता हैं और वह गरीब किसान जो हरिजन और आदिवासी हैं, दलित हैं, इस कानूनी पचड़े मे लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तो देर से ही नहीं, कुछ मित्रो ने ठीक ही कहा कि चुनाव आने वाला हैं इसलिए ये संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं ताकि इनको वोट का इजाफा हो जाए। होगा या नहीं होगा, यह बाद की बात हैं लेकिन देर से ही सही, इस काम को पहले इनको करना चाहिए था लेकिन आज भी ये संशोधन लाए हैं तो हम इनका समर्थन करते हैं और मेरा सुझाव हैं कि बेनामी और फर्जी जमील को जो लोग हड़प करके रखे हुए हैं, कुत्ते के नाम पर जमीन रखे हुए हैं, ऐसे आदमी के नाम हैं जो आदमी खोजिएगा तो पूरी पांचयत में और ब्लॉक में नहीं मिलेगा लेकिन उसके नाम पर, फर्जी नाम पर ये जमीन रखे हुए है तो यह हदबंदी कानून में जो लूपहोल्स हैं, हम चाहेंगे जगन्नाथ मिश्र जी से और इनके सरकार से कि इन लूप-होल्स को आप बंद करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा।

इसी तरह से एक और खतरा पैदा हो गया हैं इनकी उदारीकरण की आर्थिक नीति से और अखबारों में बातें आ रही हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जमीन देने जा रहे हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जमीन देने जा रहे हैं फॉर्म खोलने के लिए भारत मे। अगर इनको यह फॉर्म खोलने के लिए जमीन देंगे तो भूमिहीन और गरीब जो हैं, दलित जो हैं, उनको जमीन कहां से दे पाएंगे और किस तरह से दे पाएंगे? हम समझतें हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए जमीन देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो लोग गरीब हैं, जिनको जमीन चाहिए और गांव के जीवन से जब तक जमीन का संकेन्द्रण खत्म नहीं होगा तो गांव के जीवन से सामाजिक जुल्म का, अत्याचार का, सामाजिक शोषण का खात्मा नहीं होगा। फिर भी इस बिल का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। धन्वाद।

†**شری جلال الدین انصاری "بہار":** آدھے منٹ کے سمے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے نہیں دینا۔اس ٹائم کے کیا معنی ہیں۔

اپ سبھا ادھیکش مہودے۔میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں اسلئے کہ سات راجیوں میں بھومی سدھاربھومی حدبندی قانون لاگوکرنے کیلئے اور واستوک پرچہ دینے کا جو قانون ہے وہ سمودھان کی نو ویں "انوسوچی" میں آجانے سے کورٹ میں اسکی چنوتی نہیں دی جائیگی۔ ہم لوگوں کا "ویوہار" "انوبھو" ہے کہ سرکار نے جنکو حد بندی سے فاضل زمین دی ہے۔ پرچہ بھی دے دیا جسکو لال کاغزکہتے ہیں لیکن اس پر قبضہ نہیں دیا ہے اور وہ "لوورکورٹ" سے لیکر ھائی کورٹ تک اور "بورڈآف رونیوتک" مقدمے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آتے رہتے ہیں۔تو سرکا ر کا ان قانونوں کے مادھیم سے زمین دینے کا جو لکشے ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے اور وہ غریب کسان جو ہریجن اور آدی واسی ہیں۔ دلت ہیں جن قانونی پچڑے میں لڑنے میں اے سمرتھ ہوجاتے ہیں تودیر سے ہی صحیح

†[]Transliteration in Arabic Script

پائینگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہو راشٹریہ کمپنیوں کیلئے زمین دینے کی ویوستھا نہیں ہونی چاہئے جو لوگ غریب ہیں جنکو زمین نہیں چاہئے اور گاؤں کے جیون سے جبتک زمین کا "سنکیدرن" ختم نہیں ہوگا تو گاؤں کے جیون سے ساماجک ظلم کا۔ اتیاچار کا۔ ساماجک شوشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اس بل کے مقصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنی پارٹی۔ بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے اس بل کا پرزور سمرتھن کرتے ہیں۔ دھنیہ واد۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी, आप क्या बोलेंगे? आप अच्छा बोलते हैं, प्रभावी बोलते हैं, डेढ़ मिनट में क्या बोलेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह : रजिस्टर करा देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) : करा दीजिए। एसोसिएशन की तरह।

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार यह बिल लायी हैं, यह बिल स्वागत के काबिल हैं। उसमें हमारी कोई बहस नहीं हैं। दरअसल यह काम आज 50 साल बाद हो रहा हैं। कांग्रेस की सरकार हैं और कांग्रेस की त्रिपुरी कांग्रेस और रामगढ़ कांग्रेस दोनों मे लगातार बहस होने के बाद कांग्रेस ने यह तय किया था कि आजादी मिलेगी तो हम भूमि सुधार आन्दोलन के माध्यम से सब लोगों को जमीन बांटेगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह काम बहुत विलम्ब से हो रहा हैं और विलम्ब से काम होते-होते देश में कई ऐसे आन्दोलन खड़े हो गये हैं जिसका कोई जवाब आज तक नहीं निकल रहा हैं। मुझे डर सिर्फ एक बात का हैं, मैं बधाई तो सरकार को दे रहा हूं, लेकिन रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टरी का तालमेल बैठेगा या नहीं, यह एक गंभीरता का सवाल मेरे सामने हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐलोकेशन ...।

کچھ متروں نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ چناؤ آنے والا ہے۔ اسلئے یہ سمودھان سنشودھن ود ھیک لا رہے ہیں تا کہ انکو ووٹ کا اضہ فہ ہو جائے۔ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بعد کی بات ہے لیکن دیر سے ہی صحیح اس کام کو پہلے انکو کرنا چاہئے تھا۔ لیکن آج بھی یہ سنشودھن لائے ہیں تو ہم انکا سمرتھن کرتے ہیں اور میرا سجھاؤ ہے کہ بے نامی اور فرضی زمین کو جو لوگ ہڑپ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کتے کے نام پر زمین رکھے ہوئے ہیں ایسے آدمی کے نام ہے کہ جو آدمی کھوجئے گا تو پوری پنچایت میں اور بلاک میں نہیں ملے گا۔ لیکن اسکے نام پر۔ فرضی نام پر یہ زمین رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حد بندی قانون میں جو لوپ ہولس ہیں ہم چاہینگے جگناتھ مشرا جی سے اور انکی سرکار سے کہ ان "لوپ ہولس "کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ یا نہیں چاہتے ہیں اگر نہیں کیجئے گا تو نہیں ہوگا۔

اس طرح سے ایک اور خطرہ پیدا ہوگیا ہے انکی "اداری کرن کی آرتھک نیتی" سے اور اخباروں میں باتیں آرہی ہیں کہ یہ "بہورا شٹریہ کمپنیوں" کو زمین دینے جا رہے ہیں فارم کھولنے کیلئے بھارت میں۔ اگر انکو یہ فارم کھولنے کیلئے یہ زمین دینگے تو "بھومی ہین" اور غریب جو ہیں انکو میں کہاں سے دے پائینگے اور کس طرح سے دے

श्री दिग्विजय सिंह : ऐलोकेशन से लैंड रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं हैं। डर वह हैं जिसका अंसारी साहब ने जिक्र किया और यह सरकार का मामला नहीं हैं। देश में एक माहौल, फिजां बन रही हैं कि बड़ी जमीन के जोतदारों से ही देश में पैदावार बढ़ायी जा सकती हैं। यह माहौल बन रहा हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी बिहार के हैं। बिहार में समाजवादियों का और साम्यवादियों का, कम्यूनिस्टों का पिछले 30-40 साल से लगातार आन्दोलन चला लेकिन वह आन्दोलन भी अब समाप्त हो गया हैं, अब उस आन्दोलन में कोई दम मैं नहीं देखता हूं। इसका मतलब है कि मानसिकता बदल रही हैं। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया हैं, यह बिल लाए हैं। लेकिन इस बिल की उपयोगिता भी लोगों को देखने को मिले। बिल की सार्थकता और आवश्यकता क्या है, यह भी देखने को मिले। अब तक तो ऐसा ही होता रहा है कि जो बड़े लोग थे, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हम लोग भी ऐसे परिवार में थे जहां हम लोगों के पास बहुत जमीन थी, हजारों बीघा जमीन थी लेकिन उस जमीन का बंटवारा इतने गलत तरीके से हुआ, जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हैं। ऐसा लगता हैं कि उसका कोई मतलब नहीं था, जो नेशनल कमिटमेंट हैं हमारा, उस कमिटमेंट को पूरा करने में। आपने सही कहा कि ज्यादा समय नहीं हैं, न मैं लम्बा-चौंडा इस पर भाषण देने को तैयार हूं।

श्री वी. नारायणस्वामी : सात बिल लाए हैं बिहार से। आप देखिए ...।

श्री दिग्विजय सिंह : रामेश्वर ठाकुर जी तो अब मंत्री नहीं रहे लेकिन यह अच्छी बात हैं कि रामेश्वर ठाकुर जी भी ...(**व्यवधान**)... मेरा मतलब सरकार से हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में भी यह बहस बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने चलाई थी इसलिए बिहार के लोगों का तो यह हक हैं ही कि इस बिल के बारे में ज्यादा बोले और सौभाग्य हैं कि रामेश्वर ठाकुर जी ने इस बिल को बनाया और जगन्नाथ मिश्र जी इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई के दिनो में भी इस बिल पर और इस भूमि सुधार आन्दोलन के लिए जिस एक व्यक्ति का नाम लिया जा सकता हैं, बड़े नेताओं में कृष्ण वल्लभ सहाय जी का नाम था। आज इस बिल को जगन्नाथ मिश्र जी सदन में लाए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAM (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Hanumanthappa, you requested for two minutes' time. Okay.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, I do not want to go into land reforms. I am only on the limited issue of inclusion of these Bills in the Schedule. That is all before us. I do not want to encroach upon the time of the House.

Sir, actually, my doubt here is about one of the Bills from Karnataka which is being included in the Ninth Schedule. The Bill was enacted in 1984 and in 1995 it is entering the Ninth Schedule. In between, people have gone to court and decisions have been taken. What will be the fate of those decisions? Here I want a clear clarification from the Government.

The purpose is defeated by the delay in including these Bills in the Ninth Schedule. Dr. Biplab Das Gupta pinched us, that the Congress was sleeping. But, in between he was in the ruling party. He also slept over it. Unfortunately, throwing the blame at each other will not serve the prupose. The purpose of passing the Bill in 1984 is defeated by including it in the Ninth Schedule in 1995. This is my point. Will the Government come out with any remedy? This is number one.

Number two, the inclusion of the Acts in the Ninth Schedule prevents a party from going to the court of law, but it does not prevent the Government from further amending the law to defeat the original amendment. What is the remedy?

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Only one point of clarification. The court ruled in 1977 that the Amendment Acts should be included in the Ninth Schedule. Your Government did not include them from 1977 till date. How many years? It is nearly 20 years. ...*(Interruptions)*

' SHRI V. NARAYANASAMY: Which Government was there in 1977?

SHRI G. SWAMINATHAN: The court said in 1977 that unless the Amendment Acts were included in the Ninth Schedule, they would not have validity. From 1977 till date you have not included them. There were so many mendments. That is why this problem as tarisen. Why was your Government sleeping for so many years? It slept for nearly 18 years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Don't join issue with anybody.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: That is right. Unfortunately.

Mr. Swaminathan wants to raise an issue.

My next query is this. As I said, it prohibits a party from questioning it in a court of law, but it does not prohibit the Government from amending its own Act to defeat the original amendment. What is the remedy? As Mrs. Renuka Chowdhury put it, multinationals are coming and they are buying hundreds of acres of land, and industries are buying hundreds of acres of land, defeating the very Land Reforms Acts and Tenancy Acts. So, what is the remedy? I want the Minister to clarify these two issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Now, the hon. Minister will reply to the debate.

Mr. Minister will you kindly clarify one more point? When did the State Governments suggest to the Central Government to include these legislations in the Ninth Schedule? Was it long back, or was it recently? In the Statement of Objects and Reasons, you have said that these State Governmetns had suggested inclusion of some of their Acts relating to land reforms in the Ninth Schedule and that, therefore, these were being included therein to ensure that the implmentation of these Acts was not affected by litigation. When did you get these recommendations or suggestions from the State Governments? One, two, three, four, five or ten years ago?

DR. BIPLAB DASGUPTA: May I add just one point? The Revenue Ministers from different States... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You have made that point.

DR. BIPLAB DASGUPTA: They made their recommendations... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): That is right. I am putting the question from the Chair. Why do you repeat it unnecessarily?

Mr. Minister, if you can throw light on this, when did you get the suggestions from the State Governments to include them in the Ninth Schedule?

डा. जगन्नाथ मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के प्रति मैं आभारी हूं जिन्होने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी राय दी हैं। हमने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह कहा था कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य यही हैं कि जो मूल अधिनियम बरसों से नवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं उन विधेयकों में, उन अधिनियमों में जो समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं उन संशोधनों को भी नवीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त हो। जो पहली बार अधिनियम सम्मिलित हो जाता हैं, स्वाभाविक रूप से इन संशोधनो को वह हैसियत प्राप्त नहीं होती, वह सब्जेक्ट टु चैलेंज हो जाता हैं। इसलिए आवश्यकता होता हैं कि समय-समय पर जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों को भी नवीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त हो। जैसा जानकारी माननीय सदस्यों को हैं कि नवीं अनुसूची में ऐसी चीजों को रखने का प्रस्ताव पहली बार 1951 में हुआ जब संविधान में संशोधन हुआ। यह भी जानकारी होगी आपको कि जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम हैं जिसकी चर्चा अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे, पहली बार जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम का कांग्रेस का फैसला था। जिस रामगढ़

कांग्रेस की चर्चा और दूसरे कांग्रेस प्रस्ताव की चर्चा यह कर रहे थे उसी प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए पहली बार बिहार में भूमिसुधार कानून पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको चुनौती दी गई थी और अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसी के बाद 1951 में सविधान का जो पहला संशोधन हूआ था वह यही संशोधन हुआ। तब उस समय 13 ऐसे अधिनियमों को नवीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त हुआ। और संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन हुआ। ए, बी और सी, इसमें तीन भाग जोड़े गए जिनमें राष्ट्रीय निदेशक सिद्वांतो के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के निमित्त जो अधिनियम बनाए गए हैं, उनको समय समय पर संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, यही मूल उद्देश्य रहा हैं। उसके बाद लगातार 1955 में, 1965 में, 1972 में, 1974 में, 1975 में , और 1976 में जब कांग्रेस का शासन था, उस समय भिन्न भिन्न राज्यों को अधिनियम में सरंक्षण दिया गया। बाद में 1978 में, 1984 में और 1990 में यह संरक्षण दिया गया। जिस विधेयक को हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं उसको भी 1994 में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसलिए सरकार की तरफ से कोई उदासीनता नहीं हैं। यह जो आंशका व्यक्त की गयी हैं, यह जो आरोप व्यक्त किया गया हैं, विप्लव दास जी की तरफ से, यह सही नहीं हैं क्योंकि यह कांग्रेस की प्रतिबद्वता रही हैं और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की पूरी प्रतिबद्वता भूमि सुधार के साथ हैं और वे ग्रामीण जीवन को पूर्ण संरक्षण देना चाहते हैं, वहां का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वहां भूमि सुधार का स्थायीकरण होना चाहिए और इस समस्या का निदान होना चाहिए तथा भूमि के मामले में कोई अनिश्चिता नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए पूरा प्रयास सरकार की ओर से हो रहा हैं। आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव क्या भूमि की हदबंदी पर पड़ा रहा हैं, क्या भूमि हदबंदी की सीमा बढ़ायी जा रही हैं, इस बारे में हमने सरकार की नीति स्पष्ट की हैं। इस बारे में सरकार का सोच स्पष्ट हैं और भूमि के मामले में कोई अनिश्चतता नहीं रखी जाएगी और न उसकी कोई सीमा घटायी जाएगी और उसकी सीमा बढ़ायी जाएगी। ए1972 का जो हमारा कानून हैं उसके अनुसार यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी विप्लव दास जी चर्चा कर रहे थे की उनकी सरकार की तरफ से जो एक अधिनियम हमारे पास आया हैं जिसको हमने अपने पास रोका हुआ हैं उसके अन्तर्गत वह सरकार को अधिकार देना चाहते हैं कि किसी भी रेय्यत को हदबंदी सीमा से अधिक जमीन की इजाजत होगी। यह एक प्रतिगामी कदम हैं। हमारे राष्ट्रीय मार्ग दर्शक सिद्वांत जो निर्धारित हैं यह उसके विरूद्व हैं, जिसे पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमारे पास प्रस्ताव के रूप में भेजा हैं। यह हमारे विचारधीन हैं। इसी प्रकार से एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा हैं। उस प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा हैं। उस प्रस्ताव में भी कहा गया हैं और जिसकी चर्चा यहां पर एक माननीय सदस्य ने की हैं, उसमें लिखा हुआ हैं कि उद्योगपतियों को छूट हो कि वे सीमा से अधिक ले सकें। ऐसा हदबंदी कानून में कोई प्रावधान नहीं हैं कि उद्योगपति को जमीन की हदबंदी की सीमा से अधिक भूमि

(उपसभापति पीठासीन हुई)

रखने की इजाजत हो। हमारी एक ही सीमा हैं और 120 की सीमा हमारी निर्धारित हैं, परिभाषित हैं। इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं हैं कि बहु-राष्ट्रीय कंपनियां यहां पर आयें और जमीन अर्जित करें या खरीदें और जो हदबंदी कानून के मुख्य उद्देश्य हैं, उनको डिफीट करें। हमने यह भी प्रारंभ में कहा हैं कि जहां पर भी पब्लिक परफ्वेज के लिए राज्य सरकारों ने जमीन भूमिहीनों के लिए हैं और इस जमीन को दूसरे कार्यो में नहीं लगाया जा सकता हैं। इसलिए इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट हैं। जो हदबंदी की जमीन हैं, उस जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जा सकता हैं। इसकी इजाजत हम किसी राज्य को नहीं देने वाले हैं।

एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दो तरह के विवाद इस संबंध में हैं। एक संवैधानिक विवाद हैं और दूसरा विवाद हैं इस कानून को कार्यान्वित करने के संबंध में, इसकी प्रक्रिया के संबंध में 1 तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो विवाद हैं, जो विवाद प्रक्रिया से संबंधित हैं, उसका संरक्षण नौवी अनुसूची से होता हैं और नौंवी अनुसूचित में जो जमीन सम्मिलित हैं, यह उसको संरक्षण देती हैं। संवैधानिक आपत्तियां अगर हैं तो अधिकार के संबंध में विधान मंडल कंपीटेन्ट हैं कि नहीं, जब यह चुनौती आती हैं तो इससे उसको संरक्षण मिलता हैं। इसलिए जो 10 हजार जमीन के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचारधीन हैं वे संवैधानिक मामले नहीं हैं। वह प्रक्रिया से संबंधित हैं और जिस अधिनियम की चर्चा हनुमनतप्पा जी ने की हैं, वह प्रक्रिया से संबंधित हैं। दूसरी बात यह हैं कि जिस दिन से नवी अनुसूची का अंश यह अधिनियम बन जाएगा उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसी दिन से मिल

जाएगा। यह पहले परिभाषित हो चुका हैं कि जिस दिन नीवं अनुसूची में आ जाएगा संवैधानिक मामलों में इसको संरक्षण मिल जाएगा। इसलिए इस विषय पर जहां कहीं भी मामला लम्बित होगा, वह अपने आप निरस्त हो जाएगा जिस न्यायालय में भी होगा। इसलिए इस बात को स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि भारत सरकार की मंशा इस मामले में स्पष्ट हैं और इसे हम बड़ी तीव्रता से, मजबूती से कार्यान्वित करना चाहते हैं। यह बात उठी यहां की जमीन के रिकार्ड के बारे में । 1987-88 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होने गहराई से जमीन की समस्या को देखा था। उन्होने व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम लैंड रिकार्डिंग का बनवाया था और आधी रकम भारत सरकार से दी जा रही थी। अभी तक 104 करोड़ रूपया इन कार्यो के लिए दिया गया हैं। 1988-89 में लैंड रिकार्ड के कंपाइलेशन का कार्यक्रम भी चलाया गया जो शतप्रतिशत केन्द्रीय अनुदान हैं। अभी तक 24 करोड़ रूपया इस कार्य के लिए राज्यों को दिया गया हैं। यह राज्य सरकार का विषय हैं, इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को होगी ही कि लैंड राज्य का विषय हैं। हम राज्यों को केवल सुझाव देते हैं, मार्ग-दर्शन करते हैं। कार्यान्वयन में भारत सरकार का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता हैं। इसलिए कमियां अगर हैं तो राज्य सरकारों के स्तर पर हैं। केन्द्रीय सरकार की तरफ से समय समय पर उन्हे हम चेतावनी देते हैं, हिदायत भी देते हैं कि भूमि सुधार के कानूनों को तत्परता से लागू करिये। अभी एक राज्य के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम हदबंदी की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं। हमने तत्काल भारत सरकार की मंशा से उनको अवगत कराया कि भारत सरकार की मंशा हदबंदी बढ़ाने की नहीं हैं। इसलिए आप पुराना जो कानून हैं उसे कार्यान्वित करिये। कोई नया विवाद इस संबंध में उत्पन्न नहीं करिये। इसी तरह का सुझाव हमने दूसरे राज्यों को दिया हैं। भारत सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं और भूमि सुधार के कार्यक्रमों को समय पर पूरा किया जाए। यह ताकीद इन दिनों राज्य सरकारों को हम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इन विधेयकों के शमिल हो जाने से जैसे हमने कहा हैं कि तीन विधेयक मूल विधेयक हैं और 24 जो पुराने अधिनियम हैं, उनकी हम संरक्षण देने जा रहे हैं। राज्य सरकारों से विलम्ब से अनुशंसा प्राप्त होती रही हैं। जब एकसाथ संकलित हो जाती हैं, तभी हम नवीं अनुसूची में सम्मिलित करते हैं। पिछले साल भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव पेश हुआ था इसलिए कोई भ्रम भूमि सुधारों के संबंध नहीं हो कि भारत सरकार की मंशा में परिवर्तन होने जा रहा हैं। हम हरिजन, आदिवासियों को अधिक से अधिक लाभ देना चाहते हैं और उन्ही के लिए हमने राज्य सरकारों को कहा कि जो जमीन बांटने योग्य नहीं हैं उस जमीन को बांटने योग्य किया जाए। जो जमीन पब्लिक परपज़ के लिए ली गई हैं वह जमीन गरीबों के लिए दी जाए। जो कानूनी विवाद में फंसी हुई हैं, उसको मुक्त किया जाए जिससे हरिजनों, आदिवासियों और समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को जमीन मिल सके। 17 लाख हरिजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभान्वित किया गया हैं। 26 लाख दूसरे गरीब लोग हैं जिन्हे भूमि सुधार के कार्यक्रमों का लाभ मिला हैं। जैसे हमने प्रारम्भ में कहा कि 75 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन घोषित होने के बाद 64 लाख एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में आने के बाद 51 लाख एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में आने के बाद 51 लाख एकड़ जमीन का पूर्ण रूप से वितरण हो गया हैं, खेती योग्य हो गई हैं। जो नया ग्रामीण ढांचा बनने जा रहा हैं उससे भूमि सुधार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसे हम करना चाहते हैं। इसलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भ्रम, कोई विवाद भूमि सुधार के मामले में नहीं हो। माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उन पर हम विचार करेंगें और सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन, संशोधन की संभावना नहीं हैं, यह भ्रम नहीं रहे।

SHRI R. MARGABANDU: Madam, I just want to seek one clarification. ..*(Interruptions)*...

The hon. Minister has explained the circumstances under which the legislation is brought. Now, the question is whether this legislation is subject to judicial scrutiny. The second point is, even though these enactments are included in the Ninth Schedule, they are challenged in the court of law. Which is supreme? What is the protection for the legislation

which has been included in the Ninth Schedule? The courts are giving different judgements.

डा. जगन्नाथ मिश्र : जैसा मैंने कहा महोदया कि संवैधानिक संरक्षण दे रहे हैं, कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन टु द ला, नाट प्रोसीजरल। प्रोसीजरल तो हमेशा सब्जेक्ट टु जुडीशियल स्क्रुटिनी था ही।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes — 125 Noes — Nil

AYES-125 A

Adik, Shri Govindrao (Maharashtra)
Agarwal, Shri Lakkhiram (Madhya Pradesh)
Agarwal, Shri Satish (Rajasthan)
Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar (Bihar)
Ahluwalia, Shri S.S. (Bihar)
Alva, Shrimati Margaret (Karnataka)
Ansari, Shri Jalaludin (Bihar)
Aram, Dr. M. (Nominated)
Austin, Shri S. (Tamil Nadu)

B

Bakht, Shri Sikander (Madhya Pradesh)
Barongpa, Shri Sushil (Himachal Pradesh)
Basu, Shri Nilotpal (West Bengal)
Bhandari, Shri Ram Deo (Bihar)
Bhandari, Shri Sunder Singh (Rajasthan)
Bhardwaj, Shri Hansraj (Madhya Pradesh)
Bommai, Shri Somappa R. (Orissa)

C

Chanpuria, Shri Shivprasad (Madhya Pradesh)
Chaturvedi, Shri Bhuvnesh (Rajasthan)
Chaturvedi, Shri Triloki Nath (Uttar Pradesh)
Chavan, Shri S.B. (Maharashtra)
Chellappa, Shri V. Rajan (Tamil Nadu)

D

Dard, Shri Jagir Singh, (Punjab) Das, Shrimati Mira (Orissa) Dasgupta, Dr. Biplab (West Bengal) Deo, iShri V. Kishore Chandra S. (Andhra Pradesh) Desai, Shri Jagesh (Maharashtra) Duraisamy, Shri V.P. (Tamil Nadu) Dutta, Dr. B.B. (Nominated)

F

Fernandes, Shri John F. (Goa)

G

Ganesan, Shri Misa R. (Tamil Nadu)
Gautam, Shri Sangh Priya (Uttar Pradesh)
Ghufran Azam, Shri (Madhya Pradesh)
Gujral, Shri Inder Kumar (Bihar)
Gupta, Shri Narain Prasad (Madhya Pradesh)

H

Hanumanthappa, Shri H. (Karnataka)
Hariprasad, Shri B.K. (Karnataka) Hiphei, Shri (Mizoram)

J

Jayadevappa, Shri K.R. (Karnataka)
Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra (Maharashtra)
Jogi, Shri Ajit P.K. (Madhya Pradesh)
Joshi, Dr. Murli Manohar (Uttar Pradesh)

K

Kalita, Shri Bhubaneswar (Assam) Kalmadi, Shri Suresh (Maharashtra) Kalyan, Shri Mohindar Singh (Punjab) Kataria, Shri Virendra (Punjab) Keshri, Shri Sitaram (Bihar) Khan, Shri K.M. (Andhra Pradesh) Khan, Shri K. Rahman (Karnataka) Khan, Shri Mohd. Masud (Uttar Pradesh) Khaparde, Miss Saroj (Maharashtra)

Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. (Tamil Nadu)
Kohli, Shri O.P. (Delhi)
Kore, Shri Prabhakar B. (Karnataka)
Korwar, Shri Gundappa (Karnataka)
Kovind, Shri Ram Nath (Uttar Pradesh)

M

Mahajan, Shri Pramod (Maharashtra)
Maheshwar Singh, Shri (Himachal Pradesh)
Majumdar, Shri Sudhir Ranjan (Tripura)
Malaviya, Shri Radhakishan (Madhya Pradesh)
Malaviya, Shri Satya Prakash (Uttar Pradesh)
Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh (Gujarat)
Manian, Shri O.S. (Tamil Nadu)
Manmohan Singh, Dr. (Assam)
Margabandu, Shri R. (Tamil Nadu)
Ma tang Sinh, Shri (Assam)
Mathur, Shri Jagdish Prasad (Uttar Pradesh)
Md. Salim, Shri (West Bengal)
Miri, Shri Govindram (Madhya Pradesh)
Mishra, Dr. Jagannath (Bihar)
Mohanty, Shri Sarada (Orissa)
Moopanar, Shri G.K. (Tamil Nadu)
Mukherjee, Shri Dipankar (West Bengal)
Mukherjee, Shri Pranab (West Bengal)
Murthy, Shri M. Rajasekara (Karnataka)

N

Narayanasamy, Shri V. (Pondicherry)
Nomani, Maulana Habibur Rahman (Nominated)

P

Pachouri, Shri Suresh (Madhya Pradesh)
Pandey, Shrimati Chandra Kala (West Bengal)
Parmar, Shri Rajubhai A. (Gujarat)
Paswan, Shri Kameshwar (Bihar)
Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai (Gujarat)
Patel, Shrimati Urmilaben Chimanbhai (Gujarat)
Patil, Dr. Gopalrao Vithalrao (Maharashtra)
Pillai, Shri Thennala Balakrishna (Kerala)
Poojary, Shri Janardhana (Karnataka)
Pragada Kotaiah, Shri (Andhra Pradesh)

R

Raghavji, Shri (Madhya Pradesdh)
Ramji Lai, Shri (Haryana)
Rao, Shri V. Rajeshwar (Andhra Pradesh)
Razi, Syed Sibtey (Uttar Pradesh)
Reddy, Shri G. Prathapa (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri S. Jaipal (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri T. Venkatram (Andhra Pradesh)
Roy, Shri Joyanta (West Bengal)

S Sahu, Shri Rajni

Ranjan (Bihar) Salve, Shri N.K.P. (Maharashtra) Sanadi, Prof. I.G. (Karnataka)
Sarang, Shri Kailash Narain (Madhya Pradesh)
Sarma, Shrimati Basanti (Assam)
Satchidananda, Shri (Karnataka) Shah, Shri Viren J. (Maharashtra) Sharma, Shrimati Malti (Uttar Pradesh) Sharma, Shri Vinod (Punjab) Shastri, Shri Vishnu Kant (Uttar Pradesh)
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao (Maharashtra)
Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai (Gujarat)
Singh, Dr. Ranbir (Uttar Pradesh) Singh, Shri Raj Nath (Uttar Pradesh) Singh, Shri W. Kulabidhu (Manipur) Singla, Shri Surinder Kumar (Punjab) Solanki, Shri Gopalsinh G. (Gujarat) Solanki, Shri Madhvsinh (Gujarat)
Som Pal, Shri (Uttar Pradesh) Surjewala, Shri S.S. (Haryana) Swaminathan, Shri G. (Tamil Nadu)

T

Thakur, Shri Rameshwar (Bihar)
Topden, Shri Karma (Sikkim) Trivedi, Shri Dineshbhai (Gujarat)

U

Upendra, Shri P. (Andhra Pradesh)

V

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh (Uttar Pradesh)
Verma, Shrimati Veena (Madhya Pradesh)
Vizol, Shri (Nagaland)

Y

Yadav, Shri Naresh (Bihar)
Yerra Narayanaswamy, Shri (Andhra Pradesh)
Yonggam, Shri Nyodek (Arunachal Pradesh)

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2—there is one amendment by Dr. Mishra.

CLAUSE 2 (AMENDMENT OF THE NINTH SCHEDULE).

डा. जगन्नाथ मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि **:-**

"पृष्ठ1, पंक्ति 5 में, "प्रविष्टि 257" के स्थान पर "प्रविष्टि 275क" रखें"।

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the" Bill.

The House divided.

The Deputy Chairman: Ayes---------- 125
Noes ----- Nil

AYES—125

A

Adik, Shri Govindrao (Maharashtra) Agarwal, Shri Lakkhiram (Madhya Pradesh) Agarwal, Shri Satish (Rajasthan) Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar (Bihar) Ahluwalia, Shri S.S. (Bihar)
Alva, Shrimati Margaret (Karnataka) Ansari, Shri Jalaludin (Bihar) Aram, Dr. M. (Nominated) Austin, Shri S. (Tamil Nadu)

B

Bakht, Shri Sikander (Madhya Pradesh)
Barongpa, Shri Sushil (Himachal Pradesh) Basu, Shri Nilotpal (West Bengal) Bhandari, Shri Ram Deo (Bihar)
Bhandari, Shri Sunder Singh (Rajasthan)
Bhardwaj, Shri Hansraj (Madhya Pradesh) Bommai, Shri Somappa R. (Orissa)

C

Chanpuria, Shri Shivprasad (Madhya Pradesh) Chaturvedi, Shri Bhuvnesh (Rajasthan) Chaturvedi, Shri Triloki Nath (Uttar Pradesh) Chavan, Shri S.B. (Maharashtra)
Chellappa, Shri V. Rajan (Tamil Nadu)

D

Dard, Shri Jagir Singh (Punjab) Das, Shrimati Mira (Orissa) Dasgupta, Dr. Biplab (West Bengal) Deo, Shri V. Kishore Chandra S. (Andhra Pradesh) Desai, Shri Jagesh (Maharashtra) Duraisamy, Shri V.P. (Tamil Nadu) Dutta, Dr. B.B. (Nominated)

F

Fernandes, Shri John F. (Goa)

G

Ganesan, Shri Misa R. (Tamil Nadu)
Gautam, Shri Sangh Priya (Uttar Pradesh) Ghufran Azam, Shri (Madhya Pradesh) Gujral, Shri Inder Kumar (Bihar)
Gupta, Shri Narain Prasad (Madhya Pradesh)

H

Hanumanthappa, Shri H. (Karnataka)
Hariprasad, Shri B.K. (Karnataka) Hiphei, Shri (Mizoram)

I

J

Jayadevappa, Shri K.R. (Karnataka) Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra (Maharashtra) Jogi, Shri Ajit P.K. (Madhya Pradesh) Joshi, Dr. Murli Manohar (Uttar Pradesh)

K

Kalita, Shri Bhubaneswar (Assam) Kalmadi, Shri Suresh (Maharashtra) Kalyan, Shri Mohindar Singh (Punjab) Kataria, Shri Virendra (Punjab) Kesri, Shri Sitaram (Bihar) Khan, Shri K.M. (Andhra Pradesh) Khan, Shri K. Rahman (Karnataka) Khan, Shri Mohd. Masud (Uttar Pradesh) Khaparde, Miss Saroj (Maharashtra) Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. (Tamil Nadu) Kohli, Shri O.P. (Delhi) Kore, Shri Prabhakar B. (Karnataka) Korwar, Shri Gundappa (Karnataka) Kovind, Shri Ram Nath (Uttar Pradesh)

M

Mahajan, Shri Pramod (Maharashtra) Maheshwar Singh, Shri (Himachal Pradesh) Majumdar, Shri Sudhir Ranjan (Tripura) Malaviya, Shri Radhakishan (Madhya Pradesh) Malaviya, Shri Satya Prakash (Uttar Pradesh) Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh (Gujarat) Manian, Shri O.S. (Tamil Nadu) Manmohan Singh, Dr. (Assam) Margabandu, Shri R. (Tamil Nadu) Matang Sinh, Shri (Assam) Mathur, Shri Jagdish Prasad (Uttar Pradesh) Md. Salim, Shri (West Bengal) Miri, Shri Govindram (Madhya Pradesh) Mishra, Dr. Jagannath (Bihar) Mohanty, Shri Sarada (Orissa) Moopanar, Shri G.K. (Tamil Nadu) Mukherjee, Shri Dipankar (West Bengal) Mukherjee, Shri Pranab (West Bengal) Murthy, Shri M. Rajasekara (Karnataka)

N

Narayanasamy, Shri V. (Pondicherry) Nomani, Maulana Habibur Rahman (Nominated)

P

Pachouri, Shri Suresh (Madhya Pradesh) Pandey, Shrimati Chandra Kala (West Bengal) Parmar, Shri Rajubhai A. (Gujarat) Paswan, Shri Kameshwar (Bihar) Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai (Gujarat) Patel, Shrimati Urmilaben Chimanbhai (Gujarat) Patil, Shri Gopalrao Vithalrao (Maharashtra) Pillai, Shri Thennala Balakrishna (Kerala) Poojary, Shri Janardhana (Karnataka) Pragada Kotaiah, Shri (Andhra Pradesh)

R

Raghayji, Shri (Madhya Pradesh) Ramji Lai, Shri (Haryana) Rao, Shri V. Rajeshwar (Andhra Pradesh) Razi, Syed Sibtey (Uttar Pradesh) Reddy, Shri G. Prathapa (Andhra Pradesh) Reddy, Shri S. Jaipal (Andhra Pradesh) Reddy, Shri T. Venkatram (Andhra Pradesh) Roy, Shri Joyanta (West Bengal)

S

Sahu, Shri Rajni Ranjan (Bihar) Salve, Shri N.K.P. (Maharashtra) Sanadi, Prof. I.G. (Karnataka) Sarang, Shri Kailash Narain (Madhya Pradesh) Sarma, Shrimati Basanti (Assam) Satchidananda, Shri (Karnataka) Shah, Shri Viren J. (Maharashtra) Sharma, Shrimati Malti (Uttar Pradesh) Sharma, Shri Vinod (Punjab) Shastri, Shri Vishnu Kant (Uttar Pradesh)

Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao (Maharashtra) Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai (Gujarat) Singh, Dr. Ranbir (Uttar Pradesh) Singh, Shri Raj Nath (Uttar Pradesh) Singh, Shri W. Kulabidhu (Manipur) Singla, Shri Surinder Kumar (Punjab) Solanki, Shri Gopalsinh G. (Gujarat) Solanki, Shri Madhvsinh (Gujarat) Som Pal, Shri (Uttar Pradesh) Surjewala, Shri S.S. (Haryana) Swaminathan, Shri G. (Tamil Nadu)

T

Thakur, Shri Rameshwar (Bihar) Topden, Shri Karma (Sikkim) Trivedi, Shri Dineshbhai (Gujarat)

U

Upendra, Shri P. (Andhra Pradesh) V

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh (Uttar Pradesh) Verma, Shrimati Veena (Madhya Pradesh) Vizol, Shri (Nagaland)

Y

Yadav, Shri Naresh (Bihar) Yerra Narayanaswamy, Shri (Andhra Pradesh) Yonggam, Shri Nyodek (Arunachal Pradesh)

NOES—NIL

The motion was carried by a majority of (he total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 (Short title)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause 1. There is an amendment by Dr. Jagannath Mishra.

DR. JAGANNATH MISHRA: Madam, I beg to move:

"That at page 1, line 5, *for* the word and figure "entry 257" the word, figure and letter "entry 257A" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The House divided.

Ayes..... 125
Noes ..... Nil

AYES-125

A

Adik, Shri Govindrao (Maharashtra) Agarwal, Shri Lakkhiram (Madhya Pradesh) Agarwal, Shri Satish (Rajasthan) Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar (Bihar) Ahluwalia, Shri S.S. (Bihar) Alva, Shrimati Margaret (Karnataka) Ansari, Shri Jalaludin (Bihar) Aram, Dr. M. (Nominated) Austin, Shri S. (Tamil Nadu)

B

Bakht, Shri Sikander (Madhya Pradesh) Barongpa, Shri Sushil (Himachal Pradesh) Basu, Shri Nilotpal (West Bengal) Bhandari, Shri Ram Deo (Bihar) Bhandari, Shri Sunder Singh (Rajasthan) Bhardwaj, Shri Hansraj (Madhya Pradesh)

Bommai, Shri Somappa R. (Orissa)

C

Chanpuria, Shri Shivprasad (Madhya Pradesh) Chaturvedi, Shri Bhuvnesh (Rajasthan) Chaturvedi, Shri Triloki Nath (Uttar Pradesh) Chavan, Shri S.B. (Maharashtra) Chellappa, Shri V. Rajan (Tamil Nadu)

D

Dard, Shri Jagir Singh (Punjab)

Das, Shrimati Mira (Orissa) Dasgupta, Dr. Biplab (West Bengal) Deo, Shri V. Kishore Chandra S. (Andhra Pradesh) Desai, Shri Jagesh (Maharashtra) Duraisamy, Shri V.P. (Tamil Nadu) Dutta, Dr. B.B. (Nominated)

F

Fernandes, Shri John F. (Goa)

G

Ganesan, Shri Misa R. (Tamil Nadu) Gautam, Shri Sangh Priya (Uttar Pradesh) Ghufran Azam, Shri (Madhya Pradesh) Gujral, Shri Inder Kumar (Bihar) Gupta, Shri Narain Prasad (Madhya Pradesh)

H

Hanumanthappa, Shri H. (Karnataka) Hariprasad, Shri B.K. (Karnataka) Hiphei, Shri (Mizoram)

I

J Jayadevappa, Shri K.R. (Karnataka) Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra (Maharashtra) Jogi, Shri Ajit P.K. (Madhya Pradesh) Joshi, Dr. Murli Manohar (Uttar Pradesh)

K

Kalita, Shri Bhubaneswar (Assam) Kalmadi, Shri Suresh (Maharashtra) Kalyan, Shri Mohindar Singh (Punjab) Kataria, Shri Virendra (Punjab) Keshri, Shri Sitaram (Bihar) Khan, Shri K.M. (Andhra Pradesh) Khan, Shri K. Rahman (Karnataka) Khan, Shri Mohd. Masud (Uttar Pradesh) Khaparde, Miss Saroj (Maharashtra) Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. (Tamil Nadu) Kohli, Shri O.P. (Delhi) Kore, Shri Prabhakar B. (Karnataka) Korwar, Shri Gundappa (Karnataka) Kovind, Shri Ram Nath (Uttar Pradesh)

M

Mahajan, Shri Pramod (Maharashtra) Maheshwar Singh, Shri (Hirg^lhal Pradesh) Majumdar, Shri Sudhir Ranjan (Tripura) Malaviya, Shri Radhakishan (Madhya Pradesh) Malaviya, Shri Satya Prakash (Uttar Pradesh) Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh (Gujarat) Manian, Shri O.S. (Tamil Nadu) Manmohan Singh, Dr. (Assam) Margabandu, Shri R. (Tamil Nadu) Matang Sinh, Shri (Assam) Mathur, Shri Jagdish Prasad (Uttar Pradesh) Md. Salim, Shri (West Bengal) Miri, Shri Govindram (Madhya Pradesh) Mishra, Dr. Jagannath (Bihar) Mohanty, Shri Sarada (Orissa) Moopanar, Shri G.K. (Tamil Nadu) Mukherjee, Shri Dipankar (West Bengal) Mukherjee, Shri Pranab (West Bengal) Murthi, Shri M. Rajasekara (Karnataka)

N

Narayanasamy, Shri V. (Pondicherry) Nomani, Maulana Habibur Rahman. (Nominated)

p

Pachouri, Shri Suresh (Madhya Pradesh) Pandey, Shrimati Chandra Kala (West Bengal) Parmar, Shri Rajubhai A. (Gujarat) Paswan, Shri Kameshwar (Bihar) Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai (Gujarat) Patel, Shrimati Urmilaben Chimanbhai (Gujarat) Patil, Shri Gopalrao Vithalrao (Maharashtra) Pillai, Shri Thennala Balakrishna (Kerala) Poojary, Shri Janardhana (Karnataka) Pragada Kotaiah, Shri (Andhra Pradesh)

R

Raghavji, Shri (Madhya Pradesdh)

Ramji Lai, Shri (Haryana)
Rao, Shri V. Rajeshwar (Andhra Pradesh)
Razi, Syed Sibtey (Uttar Pradesh)
Reddy, Shri G. Prathapa (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri S. Jaipal (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri T. Venkatram (Andhra Pradesh)
Roy, Shri Joyanta (West Bengal)

S

Sahu, Shri Rajni Ranjan (Bihar)
Salve, Shri N.K.P. (Maharashtra)
Sanadi, Prof. I.G. (Karnataka)
Sarang, Shri Kailash Narain (Madhya Pradesh)
Sarma, Shrimati Basanti (Assam)
Satchidananda, Shri (Karnataka)
Shah, Shri Viren J. (Maharashtra)
Sharma, Shrimati Malti (Uttar Pradesh)
Sharma, Shri Venod (Punjab)
Shastri, Shri Vishnu Kant (Uttar Pradesh)
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao (Maharashtra)
Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai (Gujarat)
Singh, Dr. Ranbir (Uttar Pradesh)
Singh, Shri Raj Nath (Uttar Pradesh)
Singh, Shri W. Kulabidhu (Manipur)
Singla, Shri Surinder Kumar (Punjab)
Solanki, Shri Gopalsinh G. (Gujarat)
Solanki, Shri Madhvsinh (Gujarat)
Som Pal, Shri (Uttar Pradesh)
Surjewala, Shri S.S. (Haryana)
Swaminathan, Shri G. (Tamil Nadu)

T

Thakur, Shri Rameshwar (Bihar)
Topden, Shri Karma (Sikkim) Trivedi, Shri Dineshbhai (Gujarat)

U

Upendra, Shri P. (Andhra Pradesh)

V

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh (Uttar Pradesh)
Verma, Shrimati Veena (Madhya Pradesh)
Vizol, Shri (Nagaland) Y
Yadav, Shri Naresh (Bihar)
Yerra Narayanaswamy, Shri (Andhra Pradesh)
Yonggam, Shri Nyodek (Arunachal Pradesh)

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Enacting Formula. There is one amendment by Dr. Jagannath Mishra.

DR. JAGANNATH MISHRA: Madam, I beg to move:

"That at page 1, line 1, *for* the word "forty-fifth" the word "forty-sixth" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRAMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Ayes 125
Noes .....Nil

AYES-125

A

Adik, Shri Govindrao (Maharashtra)
Agarwal, Shri Lakkhiram (Madhya Pradesh)
Agarwal, Shri Satish (Rajasthan)
Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar (Bihar)

Ahluwalia, Shri S.S. (Bihar) Alva, ,Shrimati Margaret (Karnataka) Ansari, Shri Jalaludin (Bihar) Aram, Dr. M. (Nominated) Austin, Shri S. (Tamil Nadu)

B

Bakht, Shri Sikander (Madhya Pradesh)
Barongpa, Shri Sushil (Himachal Pradesh)
Basu, Shri Nilotpal (West Bengal)
Bhandari, Shri Ram Deo (Bihar)
Bhandari, Shri Sunder Singh (Rajasthan)
Bhardwaj, Shri Hansraj (Madhya Pradesh)
Bommai, Shri Somappa R. (Orissa)

C

Chanpuria, Shri Shivprasad (Madhya Pradesh)
Chaturvedi, Shri Bhuvnesh (Rajasthan)
Chaturvedi, Shri Triloki Nath (Uttar Pradesh)
Chavan, Shri S.B. (Maharashtra)
Chellappa, Shri V. Rajan (Tamil Nadu)

D

Dard, Shri Jagir Singh (Punjab) Das, Shrimati Mira (Orissa) Dasgupta, Dr. Biplab (West Bengal) Deo, Shri V. Kishore Chandra S. (Andhra Pradesh) Desai, Shri Jagesh (Maharashtra) Duraisamy, Shri V.P. (Tamil Nadu) Dutta, Dr. B.B. (Nominated)

F

Fernandes, Shri John F. (Goa)

G

Ganesan, Shri Misa R. (Tamil Nadu)
Gautam, Shri Sangh Priya (Uttar Pradesh)
Ghufran Azam, Shri (Madhya Pradesh)
Gujral, Shri Inder Kumar (Bihar)
Gupta, Shri Narain Prasad (Madhya Pradesh)

H

Hanumanthappa, Shri H. (Karnataka)
Hariprasad, Shri B.K. (Karnataka) Hiphei, Shri (Mizoram)

J

Jayadevappa, Shri K.R. (Karnataka)
Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra (Maharashtra)
Jogi, Shri Ajit P.K. (Madhya Pradesh)
Joshi, Dr. Murli Manohar (Uttar Pradesh)

K

Kalita, Shri Bhubaneswar (Assam)
Kalmadi, Shri Suresh (Maharashtra)
Kalyan, Shri Mohindar Singh (Punjab)
Kataria, Shri Virendra (Punjab)
Keshri, Shri Sitaram (Bihar)
Khan, Shri K.M. (Andhra Pradesh)
Khan, Shri K. Rahman (Karnataka)
Khan, Shri Mohd. Masud (Uttar Pradesh)
Khaparde, Miss Saroj (Maharashtra)
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. (Tamil Nadu)
Kohli, Shri O.P. (Delhi)
Kore, Shri Prabhakar B. (Karnataka)
Korwar, Shri Gundappa (Karnataka)
Kovind, Shri Ram Nath (Uttar Pradesh)

M

Mahajan, Shri Pramod (Maharashtra)
Maheshwar Singh, Shri (Himachal Pradesh)
Majumdar, Shri Sudhir Ranjan (Tripura)
Malaviya, Shri Radhakishan (Madhya Pradesh)
Malaviya, Shri Satya Prakash (Uttar Pradesh)
Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh (Gujarat)
Manian, Shri O.S. (Tamil Nadu)
Manmohan Singh, Dr. (Assam)
Margabandu, Shri R. (Tamil Nadu)
Matang Sinh, Shri (Assam)
Mathur, Shri Jagdish Prasad (Uttar Pradesh)
Md. Salim, Shri (West Bengal)
Miri, Shri Govindram (Madhya Pradesh)
Mishra, Dr. Jagannath (Bihar)
Mohanty, Shri Sarada (Orissa)
Moopanar, Shri G.K. (Tamil Nadu)
Mukherjee, Shri Dipankar (West Bengal)
Mukherjee, Shri Pranab (West Bengal)

Murthi, Shri M. Rajasekara (Karnataka)

N

Narayanasamy, Shri V. {Pondicherry)
Noraani, ..Maulana Habibur Rahman (Nominated)

P

Pachouri, Shri Suresh (Madhya Pradesh)
Pandey, Shrimati Chandra Kala (West Bengal)
Parmar, Shri Rajubhai A. (Gujarat)
Paswan, Shri Kameshwar (Bihar)
Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai (Gujarat)
Patel, Shrimati Urmilaben Chimanbhai (Gujarat)
Patil, Shri Gopalrao Vithalrao (Maharashtra)
Pillai, Shri Thennala Balakrishna (Kerala)
Poojary, Shri Janardhana (Karnataka)
Pragada Kotaiah, Shri (Andhra Pradesh)

R

Raghavji, Shri (Madhya Pradesdh)
Ramji Lai, Shri (Haryana)
Rao, Shri V. Rajeshwar (Andhra Pradesh)
Razi, Syed Sibtey (Uttar Pradesh)
Reddy, Shri G. Prathapa (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri S. Jaipal (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri T. Venkatram (Andhra Pradesh)
Roy, Shri Joyanta (West Bengal)

S

Sahu, Shri Rajni Ranjan (Bihar)
Salve, Shri N.K.P. (Maharashtra)
Sanadi, Prof. I.G. (Karnataka)
Sarang, Shri Kailash Narain (Madhya Pradesh)
Sarma, Shrimati Basanti (Assam)
Satchidananda, Shri (Karnataka)
Shah, Shri Viren J. (Maharashtra)
Sharma, Shrimati Malti (Uttar Pradesh)
Sharma, Shri Venod (Punjab)
Shastri, Shri Vishnu Kant (Uttar Pradesh)
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao (Maharashtra)
Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai (Gujarat)
Singh, Dr. Ranbir (Uttar Pradesh) Singh, Shri Raj Nath (Uttar Pradesh) Singh, Shri W. Kulabidhu (Manipur) Singla, Shri Surinder Kumar (Punjab) Solanki, Shri Gopalsinh G. (Gujarat) Solanki, Shri Madhvsinh (Gujarat) Som Pal, Shri (Uttar Pradesh) Surjewala, Shri S.S. (Haryana) Swaminathan, Shri G. (Tamil Nadu)

T

Thakur, Shri Rameshwar (Bihar)
Topden, Shri Karma (Sikkim) Trivedi, Shri Dineshbhai (Gujarat)

U

Upendra, Shri P. (Andhra Pradesh)

V

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh (Uttar Pradesh)
Verma, Shrimati Veena (Madhya Pradesh)
Vizol, Shri (Nagaland)

Y

Yadav, Shri Naresh (Bihar)
Yerra Narayanaswamy, Shri (Andhra Pradesh)
Yonggam, Shri Nyodek (Arunachal Pradesh)

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Title stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes------ 125
Noes ----- Nil

AYES-125

A

Adik, Shri Govindrao (Maharashtra)
Agarwal, Shri Lakkhiram (Madhya Pradesh)
Agarwal Shri Satish (Rajasthan)
Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar (Bihar)
Ahluwalia, Shri S.S. (Bihar)
Alva, Shrimati Margaret (Karnataka)
Ansari, Shri Jalaludin (Bihar)
Aram, Dr. M. (Nominated)
Austin, Shri S. (Tamil Nadu)

B

Bakht, Shri Sikander (Madhya Pradesh)
Barongpa, Shri Sushil (Himachal Pradesh)
Basu, Shri Nilotpal (West Bengal)
Bhandari, Shri Ram Deo (Bihar)
Bhandari, Shri Sunder Singh (Rajasthan)
Bhardwaj, Shri Hansraj (Madhya Pradesh)
Bommai, Shri Somappa R. (Orissa)

C

Chanpuria, Shri Shivprasad (Madhya Pradesh)
Chaturvedi, Shri Bhuvnesh (Rajasthan)
Chaturvedi, Shri Triloki Nath (Uttar Pradesh)
Chavan, Shri S.B. (Maharashtra)
Chellappa, Shri V. Rajan (Tamil Nadu)

D

Dard, Shri Jagir Singh (Punjab) Das, Shrimati Mira (Orissa) Dasgupta, Dr. Biplab (West Bengal) Deo, Shri V. Kishore Chandra S, (Andhra Pradesh) Desai, Shri Jagesh (Maharashtra) Duraisamy, Shri V.P. (Tamil Nadu) Dutta, Dr. B.B. (Nominated)

F

Fernandes, Shri John F. (Goa)

G

Ganesan, Shri Misa R. (Tamil Nadu)
Gautam, Shri Sangh Priya (Uttar Pradesh)
Ghufran Azam, Shri (Madhya Pradesh)
Gujral, Shri Inder Kumar (Bihar) Gupta, Shri Narain Prasad (Madhya Pradesh)

H

Hanumanthappa, Shri H. (Karnataka)
Hariprasad, Shri B.K. (Karnataka) Hiphei, Shri (Mizoram)

J

Jayadevappa, Shri K.R. (Karnataka)
Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra (Maharashtra)
Jogi, Shri Ajit P.K. (Madhya Pradesh)
Joshi, Dr. Murli Manohar (Uttar Pradesh)

K

Kalita, Shri Bhubaneswar (Assam)
Kalmadi, Shri Suresh (Maharashtra)
Kalyan, Shri Mohindar Singh (Punjab)
Kataria, Shri Virendra (Punjab)
Keshri, Shri Sitaram (Bihar)
Khan, Shri K.M. (Andhra Pradesh)
Khan, Shri K. Rahman (Karnataka)
Khan, Shri Mohd. Masud (Uttar Pradesh)
Khaparde, Miss Saroj (Maharashtra)
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. (Tamil Nadu)
Kohli, Shri O.P. (Delhi)
Kore, Shri Prabhakar B. (Karnataka)
Korwar, Shri Gundappa (Karnataka)
Kovind, Shri Ram Nath (Uttar Pradesh)

M

Mahajan, Shri Pramod (Maharashtra)
Maheshwar Singh, Shri (Himachal Pradesh)
Majumdar, Shri Sudhir Ranjan (Tripura)
Malaviya, Shri Radhakishan (Madhya Pradesh)
Malaviya, Shri Satya Prakash (Uttar Pradesh)
Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh (Gujarat)
Manian, Shri O.S. (Tamil Nadu)
Manmohan Singh, Dr. (Assam)
Margabandu, Shri R. (Tamil Nadu)
Matang Sinh, Shri (Assam)

Mathur, Shri Jagdish Prasad (Uttar Pradesh)
Md. Salim, Shri (West Bengal)
Miri, Shri Govindram (Madhya Pradesh)
Mishra, Dr. Jagannath (Bihar)
Mohanty, Shri Sarada (Orissa)
Moopanar, Shri G.K. (Tamil Nadu)
Mukherjee, Shri Dipankar (West Bengal)
Mukherjee, Shri Pranab (West Bengal)
Murthi, Shri M. Rajasekara (Karnataka)

N

Narayanasamy, Shri V. (Pondicherry)
Nomani, Maulana Habibur Rahman (Nominated)

P

Pachouri, Shri Suresh (Madhya Pradesh)
Pandey, Shrimati Chandra Kala (West Bengal)
Parmar, Shri Rajubhai A. (Gujarat)
Paswan, Shri Kameshwar (Bihar)
Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai (Gujarat)
Patel, Shrimati Urmilaben Chimanbhai (Gujarat)
Patil, Shri Gopalrao Vithalrao (Maharashtra)
Pillai, Shri Thennala Balakrishna (Kerala)
Poojary, Shri Janardhana (Karnataka)
Pragada Kotaiah, Shri (Andhra Pradesh)

R

Raghavji, Shri (Madhya Pradesdh)
Ramji Lai, Shri (Haryana)
Rao, Shri V. Rajeshwar (Andhra Pradesh)
Razi, Syed Sibtey (Uttar Pradesh)
Reddy, Shri G. Prathapa (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri S. Jaipal (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri T. Venkatram (Andhra Pradesh)
Roy, Shri Joyanta (West Bengal)

S

Sahu, Shri Rajni Ranjan (Bihar) Salve, Shri N.K.P. (Maharashtra) Sandi, Prof. I.G. (Karnataka) Sarang, Shri Kailash Narain (Madhya Pradesh)
Sarma, Shrimati Basanti (Assam)
Satchidananda, Shri (Karnataka)
Shah, Shri Viren J. (Maharashtra)
Sharma, Shrimati Malti (Uttar Pradesh)
Sharma, Shri Vinod (Punjab)
Shastri, Shri Vishnu Kant (Uttar Pradesh)
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao (Maharashtra)
Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai (Gujarat)
Singh, Dr. Ranbir (Uttar Pradesh)
Singh, Shri Raj Nath (Uttar Pradesh)
Singh, Shri W. Kulabidhu (Manipur)
Singla, Shri Surinder Kumar (Punjab)
Solanki, Shri Gopalsinh G. (Gujarat)
Solanki, Shri Madhvsinh (Gujarat)
Som Pal, Shri (Uttar Pradesh)
Surjewala, Shri S.S. (Haryana)
Swaminathan, Shri G. (Tamil Nadu)

T

Thakur, Shri Rameshwar (Bihar)
Topden, Shri Karma (Sikkim) Trivedi, Shri Dineshbhai (Gujarat)

U

Upendra, Shri P. (Andhra Pradesh)

V

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh (Uttar Pradesh)
Verma, Shrimati Veena (Madhya Pradesh)
Vizol, Shri (Nagaland)

Y

Yadav, Shri Naresh (Bihar)
Yerra Narayanaswamy, Shri (Andhra Pradesh)
Yonggam, Shri Nyodek (Arunachal Pradesh)

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Title was added to the Bill.

DR. JAGANNATH MISHRA: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion to vote. The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The House divided. THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes ... 125

Noes ... Nil

AYES — 125 A Adik, Shri Govindrao (Maharashtra) Agarwal, Shri Lakkhiram (Madhya Pradesh)
Agarwal, Shri Satish (Rajasthan) Agarwalla, Shri Parmeshwar Kumar (Bihar)
Ahluwalia, Shri S.S. (Bihar) Alva, Shrimati Margaret (Karnataka) Ansari, Shri Jalaludin (Bihar) Aram, Dr. M. (Nominated) Austin, Shri S. (Tamil Nadu)

B

Bakht, Shri Sikander (Madhya Pradesh)
Barongpa, Shri Sushil (Himachal Pradesh)
Basu, Shri Nilotpal (West Bengal)
Bhandari, Shri Ram Deo (Bihar)
Bhandari, Shri Sunder Singh (Rajasthan)
Bhardwaj, Shri Hansraj (Madhya Pradesh)
Bommai, Shri Somappa R. (Orissa)

C

Chanpuria, Shri Shivprasad (Madhya Pradesh)
Chaturvedi, Shri Bhuvnesh (Rajasthan)
Chaturvedi, Shri Triloki Nath (Uttar Pradesh)
Chavan, Shri S.B. (Maharashtra)
Chellappa, Shri V. Rajan (Tamil Nadu)

D

Dard, Shri Jagir Singh (Punjab)
Das, Shrimati Mira (Orissa)
Dasgupta, Dr. Biplab. (West Bengal)
Deo, Shri V. Kishore Chandra S. (Andhra Pradesh)
Desai, Shri Jagesh (Maharashtra)
Duraisamy, Shri V.P. (Tamil Nadu) Dutta, Dr. B.B. (Nominated)

F

Fernandes, Shri John F. (Goa)

G

Ganesan, Shri Misa R. (Tamil Nadu)
Gautam, Shri Sangh Priya (Uttar Pradesh)
Ghufran Azam, Shri (Madhya Pradesh)
Gujral, Shri Inder Kumar (Bihar)
Gupta, Shri Narain Prasad (Madhya Pradesh)

H .

Hanumanthappa, Shri H. (Karnataka)
Hariprasad, Shri B.K. (Karnataka) Hiphei, Shri (Mizoram)

J

Jayadevappa, Shri K.R. (Karnataka)
Jichkar, Dr. Shrikant Ramchandra (Maharashtra)
Jogi, Shri Ajit P.K. (Madhya Pradesh)
Joshi, Dr. Murli Manohar (Uttar Pradesh)

K

Kalita, Shri Bhubaneswar (Assam)
Kalmadi, Shri Suresh (Maharashtra)
Kalyan, Shri Mohindar Singh (Punjab)
Kataria, Shri Virendra (Punjab)
Keshri, Shri Sitaram (Bihar)
Khan, Shri K.M. (Andhra Pradesh)
Khan, Shri K. Rahman (Karnataka)
Khan, Shri Mohd. Masud (Uttar Pradesh)
Khaparde, Miss Saroj (Maharashtra)
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. (Tamil Nadu)
Kohli, Shri O.P. (Delhi)
Kore, Shri Prabhakar B. (Karnataka)

Korwar, Shri Gundappa (Karnataka) Kovind, Shri Ram Nath (Uttar Pradesh)

M

Mahajan, Shri Pramod (Maharashtra)
Maheshwar Singh, Shri (Himachal Pradesh)
Majumdar, Shri Sudhir Ranjan (Tripura)
Malaviya, Shri Radhakishan (Madhya Pradesh)
Malaviya, Shri Satya Prakash (Uttar Pradesh)
Mangrola, Shri Kanaksinh Mohansinh (Gujarat)
Manian, Shri O.S. (Tamil Nadu)
Manmohan Singh, Dr. (Assam)
Margabandu, Shri R. (Tamil Nadu)
Matang Sinh, Shri (Assam)
Mathur, Shri Jagdish Prasad (Uttar Pradesh)
Md. Salim, Shri (West Bengal)
Miri,.Shri Govindram (Madhya Pradesh)
Mishra, Dr. Jagannath (Bihar)
Mohanty, Shri Sarada (Orissa)
Moopanar, Shri "O.K. (Tamil Nadu)
Mukherjee, Shri Dipankar (West Bengal)
Mukherjee, Shri Pranab (West Bengal)
Murthi, Shri M. Rajasekara (Karnataka)

N

Narayanasamy, Shri V. (Pondicherry)
Nomani, Maulana Habibur Rahman (Nominated)

P

Pachouri, Shri Suresh (Madhya Pradesh)
Pandey, Shrimati Chandra Kala (West ^Bengal)
Parmar, Shri Rajubhai A. (Gujarat) Paswan, Shri Kameshwar (Bihar) Patel, Shrimati Anandiben Jethabhai (Gujarat)
Patel, Shrimati Urmilaben Chimanbhai (Gujarat)
Patil, Shri Gopalrao Vithalrao (Maharashtra)
Pillai, Shri Thennala Balakrishna (Kerala)
Poojary, Shri Janardhana (Karnataka)
Pragada Kotaiah, Shri (Andhra Pradesh")

R

Raghavji, Shri (Madhya Pradesdh)

Ramji Lai, Shri (Haryana)
Rao, Shri V. Rajeshwar (Andhra Pradesh)
Razi, Syed Sibtey (Uttar Pradesh)
Reddy, Shri G. Prathapa (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri S. Jaipal (Andhra Pradesh)
Reddy, Shri T. Venkatram (Andhra Pradesh)
Roy, Shri Joyanta (West Bengal)

S

Sahu, Shri Rajni Ranjan (Bihar)
Salve, Shri N.K.P. (Maharashtra)
Sandi, Prof. I.G. (Karnataka)
Sarang, Shri Kailash Narain (Madhya Pradesh)
Sarma, Shrimati Basanti (Assam)
Satchidananda, Shri (Karnataka)
Shah, Shri Viren J. (Maharashtra)
Sharma, Shrimati Malti (Uttar Pradesh)
Sharma, Shri Vinod (Punjab)
Shastri, Shri Vishnu Kant (Uttar Pradesh)
Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao (Maharashtra)
Shukla, Shri Chimanbhai Haribhai (Gujarat)
Singh, Dr. Ranbir (Uttar Pradesh)
Singh, Shri Raj Nath (Uttar Pradesh)
Singh, Shri W. Kulabidhu (Manipur)
Singla, Shri Surinder Kumar (Punjab)
Solanki, Shri Gopalsinh G. (Gujarat)
Solanki, Shri Madhvsinh (Gujarat)
Som Pal, Shri (Uttar Pradesh)
Surjewala, Shri S.S. (Haryana)
Swaminathan, Shri G. (Tamil Nadu)

T

Thakur, Shri Rameshwar (Bihar)
Topden, Shri Karma (Sikkim) Trivedi, Shri Dineshbhai (Gujarat)

U

Upendra, Shri P. (Andhra Pradesh)

V

Varma, Prof. Ram Bakhsh Singh (Uttar Pradesh)

Verma, Shrimati Veena (Madhya Pradesh)
Vizol, Shri (Nagaland)

Y

Yadav, Shri Naresh (Bihar)
Yerra Narayanaswamy, Shri (Andhra Pradesh)
Yonggam, Shri Nyodek (Arunachal Pradesh)

NOES — NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Regarding the Vohra Committee Report, ... *(interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Madam, we can take it up toramorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You don't want ...*(interruptions)*... The House does not want to sit.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): Madam, what about Special Mentions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We can take up Special Mentions tomorrow. ...*(interruptions)*... Tomorrow we will take up Special Mentions. All the Special Mentions left over, everything we will take up tomorrow. So, I adjourn the House till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-one minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 23rd August, 1995.